घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर, वर्ष 23, अंक - 05- गुरूवार 05- नवम्बर 2026,पृष्ठ - 8 , मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

अग्निवीरों का कार्यकाल 2 साल

बढ़ा...अब 6 साल नौकरी कर सकेंगे

25 प्रतिशत को परमानेंट करने का नियम बना रहेगा,देश में 3.18 लाख अग्निवीर

नई दिल्ली,04 नवम्बर 2026। अग्निवीर अब चार की बजाय छह साल तक सेना में नौकरी कर सकेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बुधवार को दो साल का सेवा विस्तार देने का ऐलान किया। इसका फायदा उन 75% अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्हें पहले चार साल बाद सेवा छोड़नी पड़ती थी। अभी हर बैच के 25% अग्निवीरों को चार साल बाद मेरिट के आधार पर नियमित सेना में शामिल किया जाता है। बाकी 75% को सेवा से बाहर होना पड़ता है। नए नियम में 25% अग्निवीरों को नियमित करने का पुराना नियम जारी रहेगा। बाकी 75% को उनकी सहमति से दो साल और नौकरी करने का मौका मिलेगा। इस दौरान उन्हें बढ़ी हुई सैलरी और भत्ते भी मिलेंगे। छह साल बाद भी सेना में नौकरी करने के इच्छुक अग्निवीरों को चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। फिलहाल तीनों सेनाओं में करीब 3.18 लाख अग्निवीर सेवा दे रहे हैं।

दिसंबर तक 18,300 अग्निवीरों का कार्यकाल पूरा होना था...

आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर तक पहले बैच के करीब 18,300 अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ये पहले बैच में भर्ती हुए 24,400 अग्निवीरों का करीब 75% हैं। पहले तय योजना के मुताबिक नवंबर के मध्य से 75% अग्निवीरों को चरणबद्ध तरीके से सेवा से बाहर किया जाना था। नई व्यवस्था के तहत अब इन्हें दो साल का अतिरिक्त समय मिलेगा। यह सेवा विस्तार अग्निवीरों की सहमति से होगा।

एयरफोर्स ने पहले बैच के 712 अग्निवीरों को परमानेंट किया

पिछले महीने एयरफोर्स ने अपने पहले अग्निवीर बैच के 2,850 रिक्रूट्स में से 712 को नियमित सेवा में बनाए रखने का फैसला किया था।



दो साल की विस्तारित सेवा अवधि में अग्निवीरों को ज्यादा पैसा मिलेगा

सीडीएस ने कहा कि कैबिनेट ने दो साल की इस अवधि को मंजूरी दी है। चयन का दायरा बढ़ चुका है। सभी जिलों से अग्निवीर आ रहे हैं। पारदर्शिता के लिए अब पहले लिखित परीक्षा ली जा रही है, फिर फिजिकल टेस्ट ले रहे हैं। चार वर्षों की अवधि में अग्निवीरों की फिजिकल फिटनेस,हौसला और अनुशासन उच्च स्तर का रहा है। उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। 10वीं पास अग्निवीरों को आगे की पढ़ाई कराई गई है। फीडबैक और समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया कि 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल की अवधि और दी जाएगी। इसके तहत उन्हें ज्यादा पारितोषिक और विस्तारित सेवा निधि मिलेगी। इसी के साथ कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए यह मार्ग प्रशस्त कर दिया है कि वे सशस्त्र बलों में समाहित हो सकें।

देश में 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनेंगी

बिजली स्टोर करने की क्षमता बढ़ाने के लिए 14,500 करोड़ रुपए मंजूर

नई दिल्ली,04 नवम्बर 2026। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें यौन शोषण-रेप केसों के जल्द निपटारे के लिए 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बिजली स्टोर करने के लिए कैबिनेट ने 92 गीगावाट-घंटे क्षमता वाली ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी योजना के लिए 14,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा डेटा कलेक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 4,371 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही क्रिटिकल खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए भी एक योजना स्वीकृत की गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 92 गीगावाट-घंटे ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी योजना को मंजूरी देने का उद्देश्य बिजली को बड़े पैमाने पर स्टोर करना है, ताकि जरूरत के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके।

92 गीगावाट-घंटे की कुल क्षमता को तीन हिस्सों में बांटा गया है...

- 30 गीगावाट-घंटेः बैटरी बेस्ड एनर्जी स्टोरेज।
- 60 गीगावाट-घंटेः पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स।
- 2 गीगावाट-घंटेः नई सोलर टेक्नोलॉजी।

उन्होंने आगे कहा...एनर्जी स्टोरेज से बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता का भी बेहतर इस्तेमाल होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 10 मेगावाट की ट्रांसमिशन क्षमता बनाई गई है,तो रात में सौर बिजली नहीं बनने के कारण उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन स्टोरेज की सुविधा होने पर दिन में जमा की गई बिजली बाद में उपयोग की जा सकती है।



क्रिटिकल खनिजों की प्रोसेसिंग को मंजूरी

वैष्णव ने कहा...कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की प्रोसेसिंग की योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद खदानों से निकाले गए या कच्चे खनिजों को इस तरह तैयार करना है कि उनका इस्तेमाल सीधे उत्पादन प्रक्रिया में किया जा सके। उन्होंने बताया कि यह योजना पहचान किए गए सभी 24 महत्वपूर्ण खनिजों पर लागू होगी। इसमें खदानों से मिलने वाले खनिजों के साथ-साथ रीसाइक्लिंग से प्राप्त खनिज भी शामिल हैं।

डेटा कलेक्शन सिस्टम के लिए 4,371 करोड़ रुपए मंजूर

कैबिनेट ने देश के डेटा कलेक्शन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 4,371 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सरकारी आंकड़े जुटाने और उनकी जांच करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत सर्वेक्षण के तरीकों में सुधार किया जाएगा। आंकड़े जुटाने में होने वाली गलतियों को कम किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज में डेटा कलेक्शन से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएंगे। डेटा को नियमित रूप से जुटाने और उनकी समय-समय पर समीक्षा करने पर जोर दिया जाएगा।

सेना को मिले 450 स्वदेशी नागास्त्र-1

एंटी-टैंक लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम

नई दिल्ली,04 नवम्बर 2026। दुश्मन के सबसे मजबूत टैंकों को भी पलभर में नष्ट करने की क्षमता वाले घातक हथियार स्वदेशी नागास्त्र-1एंटी-टैंक लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम भारतीय सेना को मिल गए हैं। इसे बनाने वाली नागपुर की कंपनी सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड ने दूसरी खेप में 450 यूनिट सौंपी है। जीपीएस से लैस यह आत्मघाती ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर दो मीटर की दूरी पर सटीकता के साथ हमला करके तबाही मचा सकता है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए नागास्त्र-1 का इस्तेमाल किया था।

भारतीय सेना 450 नागास्त्र-1आर लोइटरिंग युद्ध सामग्री का ऑर्डर देकर अपनी सटीक हमला क्षमताओं को बढ़ा रही है। जीपीएस से लैस इन स्वदेशी 'आत्मघाती ड्रोन' में सटीकता के साथ हमले करने की क्षमता,उच्च ऊंचाई पर संचालन और दिन-रात निगरानी की सुविधा है। दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया यह हथियार देश के सैन्य ढांचे को और मजबूत करेगा। इस



सिस्टम का परीक्षण लद्दाख और उत्तर प्रदेश में झांसी के पास बबीना सहित विभिन्न स्थानों पर किया गया है। आने वाले समय में ऐसे और भी अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार सेना को मिल सकते हैं। नागपुर की सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड में निर्मित अत्याधुनिक लोइटरिंग म्यूनिशन नागास्त्र-1आर की पहली खेप जून 2024 में भारतीय सेना को सौंपी गई थी। सेना ने पहली खेप में मिले 120 हथियारों का इस्तेमाल 'ऑपरेशन सिंदूर'के दौरान पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया था। इस हथियार की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सेना ने अपनी सटीक हमला क्षमताओं को बढ़ाने, अपनी पैदल सेना को आधुनिक बनाने के लिए आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत 450 नागास्त्र-1आर लोइटरिंग युद्ध सामग्री का ऑर्डर दिया था,जिसकी आपूर्ति पिछले माह हुई है।

सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड में निर्मित लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम में 80 फीसदी से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। इसे आम भाषा में 'घूमकर हमला करने वाला हथियार' कहा जा सकता है,क्योंकि यह एक तरह से हवाई एंबुश यानी घात लगाकर हमला करता है।

दुश्मन के इलाके में उड़कर पहुंचने के बाद यह लक्ष्य के ऊपर हवा में मंडराता है और जैसे ही सही मौका मिलता है। यह सटीक निशाना लगाकर दुश्मन को खत्म कर सकता है। खास बात यह है कि अगर हमला रद्द करना हो,तो इसे वापस भी बुलाया जा सकता है। जिससे यह दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

राहुल गांधी ने पीएम को बहस की चुनौती दी

बोले...मोदी देशद्रोही,1 साल में निपट जाएगी सरकार,पंजाब में कत्ल करना फैशन बना

संगरूर,04 नवम्बर 2026। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को डिबेट की चुनौती दी है। मैंने उन्हें कहा है कि कहीं भी आकर मेरे साथ डिबेट कर लो, लेकिन वह मेरे सामने आकर बैठ नहीं सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि 5 मिनट में उन्हें देशद्रोही साबित कर दूंगा। मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नियत्रंति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा अनुमान है कि मोदी सरकार एक साल में निपट जाएगी। 3 साल बाद अमित शाह होम मिनिस्टर नहीं होंगे। ये बातें उन्होंने पंजाब के संगरूर में इंसाफ रैली के दौरान कही। संबोधन की शुरुआत में वह पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को स्टेज पर लाए। राहुल गांधी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के साथ जो हुआ, वह आज पंजाब में एक फैशन बन गया है। पंजाब में नशा सबसे बड़ा मुद्दा है। भगवंत मान दिल्ली में थे तो हमें चुटकुले सुनाते थे। सुबह 11 बजे उनके मुंह से शराब की बदबू आती थी। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर पीएम को बहस की चुनौती दी।

खड़गे बोले...दिल्ली में वोट चोरों की सरकार है...

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में वोट चोरी हुई है और कई जगह वोट चोरों की सरकार चल रही है। उन्होंने दिल्ली में बैठी सरकार वोट चोरों की सरकार है।



राहुल ने पीएम मोदी को दी बहस की चुनौती

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर बहस की चुनौती देते हुए कहा कि मोदी जी, आप जहां चाहें,मैं बहस के लिए तैयार हूं। मेरे सामने बैठ जाइए,दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा

राहुल गांधी ने कहा...कांग्रेस की सरकार बनाइए...

राहुल गांधी ने पंजाब के लोगों से कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि पंजाब को पंजाब की सरकार दीजिए। कांग्रेस की सरकार दीजिए। ऐसी सरकार चुनिए जो नशे के खिलाफ लड़े, ड्रग्स खत्म करे,युवाओं को रोजगार दे,उद्योगों को बचाए और किसानों के साथ खड़ी रहे। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 24 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह कहते रहते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाया था। अडाणी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे मामले को भी डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बाद बंद करवा दिया।

मोदी को ट्रम्प नियंत्रित करते हैं

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नियंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि पांच मिनट में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए और भारत के किसानों,उद्योगों तथा डेटा को अमेरिकी हितों के हवाले कर दिया गया।

राहुल बोले...मोदी मेरे साथ बहस करें

राहुल ने कहा...उन्होंने कहा कि मोदी अरबपतियों और अडाणी के लिए काम करते हैं। सब कुछ उनके हवाले किया जा रहा है, जबकि किसानों और उद्योगों के हितों की अनदेखी हो रही है। मोदी कांग्रेस नेताओं को देशद्रोही कहते हैं। मैंने उन्हें चुनौती दी है कि वह कहीं भी मेरे साथ बैठकर बहस कर लें। बीच में कोई भी जज बन सकता है,चाहे मोहन भागवत हों या अडाणी। प्रधानमंत्री उनके सामने बैठकर बहस नहीं कर सकते। संसद में जब चर्चा की मांग करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है और बोलने नहीं दिया जाता।

उद्योगों को दोबारा मजबूत करेगी कांग्रेस

राहुल गांधी ने कहा कि एक समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार के दौरान छोटे और मध्यम उद्योगों का मजबूत आधार था। किसानों और उद्योगों को मजबूत किए बिना गैंगस्टरवाद और नशे के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। कांग्रेस किसानों की रक्षा करने और उद्योगों को दोबारा शुरू करने का काम कर सकती है। भगवंत मान सरकार ने किसानों को एमएसपी देने और महिलाओं को चार साल तक आर्थिक सहायता देने का वादा किया था, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। सरकार लंबे-लंबे भाषण देती है,जबकि किसान पंजाब की रीढ़ हैं।

चुनाव आयुक्तों को आजीवन छूट के खिलाफ याचिका

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-चुनाव आयोग को नोटिस 2023 एक्ट की धारा-16 के तहत इम्यूनिटी मिली है...



नई दिल्ली,04 नवम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयुक्तों को आजीवन मिलने वाली कानूनी छूट को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। 2023 की धारा 16 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को अपने सरकारी कामकाज के दौरान किए गए फैसलों के लिए आपराधिक मुकदमों से आजीवन कानूनी सुरक्षा दी गई है। याचिका में धारा 16 पर सवाल उठाया गया है कि क्या चुनाव आयुक्तों को इस तरह कानूनी कार्रवाई से छूट देना संविधान के अनुरूप है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी. महादेवन की पीठ ने यह नोटिस जारी किया। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और वकील अरुण कुमार अग्रवाल ने दायर की है। कोई अदालत मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनके आधिकारिक काम से जुड़े मामले में दीवानी या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती। यदि ऐसी कार्यवाही पहले से चल रही है, तो अदालत उसे आगे भी जारी नहीं रख सकती। यह सुरक्षा सिर्फ पद पर रहते हुए नहीं,बल्कि पद छोड़ने के बाद भी लागू रहती है। यह संरक्षण उन कामों पर लागू है जो अधिकारी ने चुनाव आयुक्त के पद पर रहते के दौरान किए हैं।

दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव से रोकना गलत कानून पर विचार की जरूरत : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,04 नवम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। कोर्ट ने बताया कि भारत की कुल प्रजनन दर 2003 में 3 थी, जो अब घटकर 1.9 रह गई है। 2.1 की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है। इससे कम प्रजनन दर का मतलब है कि एक पीढ़ी अपनी जगह अगली पीढ़ी को पूरी तरह नहीं ले पाएगी। कोर्ट ने कहा कि प्रजनन दर में गिरावट से बुजुर्गों की आबादी बढ़ सकती है और कामकाजी लोगों की संख्या घट सकती है। इन बदलावों को नजरअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव को राहत दी। उन्हें तीसरे बच्चे के जन्म के कारण अयोग्य ठहराया गया था। बेंच ने 2003 के उस फैसले पर दोबारा विचार के लिए मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया, जिसमें दो बच्चों की शर्त को सही ठहराया गया था।

कोर्ट बोला...मौजूदा कानून राजनीतिक अधिकारों से वंचित करते हैं...

बेंच ने कहा कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून नागरिकों के एक पूरे वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर कर देते हैं। इसका किसी व्यक्ति की सार्वजनिक पद संभालने की क्षमता से कोई खास संबंध नहीं है। कोर्ट के मुताबिक, ऐसे कानून लोगों को बच्चे पैदा करने या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर करते हैं। इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले प्रजनन से जुड़े फैसले लेने की आजादी के अधिकार का उल्लंघन होता है।



महाराष्ट्र में तीसरे बच्चे के कारण महिला को अयोग्य ठहराया गया था

ममंगला भीमराव महाराष्ट्र की काकोड़ा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच थीं। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(जे-1) के तहत दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान है। इसी नियम के तहत तीसरे बच्चे के जन्म के बाद उनके खिलाफ शिकायत की गई थी। अतिरिक्त कलेक्टर ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त के पास अपील की,लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 अगस्त 2025 को उनकी अयोग्यता बरकरार रखी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है,ताकि यह तय किया जा सके कि दो बच्चों की शर्त को सही ठहराने वाले पुराने फैसले पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए या नहीं।

होर्मुज से भारतीय जहाजों को गुजरने देगा ईरान...8 महीने से बंद था रास्ता,इसी रूट से 40% कच्चा तेल मंगाता है भारत

तेहरान,04 नवम्बर 2026। ईरान ने करीब 8 महीने बाद भारतीय जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की छूट दे दी है। अब भारतीय जहाज इस रास्ते से बिना किसी रोक-टोक के गुजर सकेंगे। ईरान ने चीन, इराक और कतर के जहाजों को भी यह छूट दी है। 28 फरवरी से इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियां लगी हुई थीं। भारत अपने कुल कच्चे तेल आयात का करीब 40% इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान की न्यूज वेबसाइट ईरानवायर और अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के उपाध्यक्ष अहमद हयात-मोगद्दम ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।



भारत को दवाओं की सप्लाई के लिए मिली छूट...

रिपोर्ट के मुताबिक,ईरान ने भारत को यह छूट इसलिए दी है, ताकि उसे भारत से दवाएं मिलती रहें। वहीं,चीन को छूट देने के पीछे ईरान की उम्मीद है कि मुश्किल वक्त में बीजिंग उसका राजनीतिक रूप से साथ देगा। हालांकि, भारतीय और चीनी जहाजों को होर्मुज से गुजरने के लिए पैसे देने होंगे। वहीं, कतर के जहाज बिना कोई शुल्क दिए इस रास्ते से गुजर सकेंगे। इराक को किस वजह से छूट दी गई है,यह साफ नहीं किया गया है।

भारत के लिए क्यों अहम है होर्मुज स्ट्रेट

भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। इसमें से करीब 40% तेल होर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से भारत आने वाले तेल के लिए यह अहम रास्ता है। अगर भारत रोजाना 50 लाख बैरल कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है, तो इसमें करीब 20 लाख बैरल तेल होर्मुज के रास्ते आता है। ऐसे में इस रास्ते पर पाबंदी लगने से भारत की तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। होर्मुज सिर्फ कच्चे तेल के लिए ही जरूरी नहीं है। भारत खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में एलएनजी यानी प्राकृतिक गैस और एलपीजी यानी रसोई गैस भी मंगाता है।

संपादकीय

घुसपैठिए मतदाता

दिल्ली में विपक्ष की रैली के ठीक अगले दिन हैदराबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं और विशेष रूप से राहुल गांधी को जिस तरह निशाने पर लिया,उससे यह साफ है कि सत्तापक्ष उनके दुष्प्रचार आधारित दबाव में आने के बजाय उनके झूठे नैरेटिव का प्रतिकार करने को प्रतिबद्ध है। मतदाता सूचियों के शुद्धीकरण की प्रक्रिया यानी एसआइआर के तहत जारी मसौदा सूची से करीब 13 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटाने को विपक्ष केवल वोट चोरी बताने में ही नहीं लगा,बल्कि इस मामले में वकील संग जज भी बना हुआ है। वह यह सुनने-समझने को तैयार नहीं कि इन 13 करोड़ लोगों में 6.30 करोड़ वे हैं, जो स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित हो गए,करीब 2.80 करोड़ वे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है,एक करोड़ से अधिक के नाम दो या तीन जगह दर्ज थे और लगभग तीन करोड़ लोग सत्यापन के समय अपने पते पर मिले ही नहीं। गृहमंत्री ने दो टूक कहा कि ये तीन करोड़ वस्तुतः घुसपैठिए हैं और इनके नाम वोटर लिस्ट से बाहर होकर रहेंगे। उनका यह दावा इसलिए सच जान पड़ता है, क्योंकि ऐसे तीन करोड़ लोगों के बारे में उनके पड़ोसी भी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।

आखिर विपक्ष इस पर क्यों तुला है कि जो अन्यत्र बस गए या मर गए अथवा जिनके नाम एक से अधिक जगह दर्ज हैं और जो खोजने पर भी नहीं मिल रहे हैं,उनका नाम वोटर लिस्ट में क्यों होना चाहिए? वह इस सच से अनजान नहीं कि देश में दशकों से बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई है और उन्होंने बंगाल,असम,त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में डेमोग्राफी भी बदल दी है। कांग्रेस,वामदल और तृणमूल कांग्रेस तो यह कहीं अच्छे से जानते हैं कि असंख्य बांग्लादेशियों ने छल-छद्म से हर तरह के पहचान पत्र प्राप्त कर खुद को भारतीय नागरिक में तब्दील कर लिया है,क्योंकि इन दलों ने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उन्हें संरक्षण देकर अपना वोट बैंक बनाया।

इसी कारण बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अवैध बांग्लादेशी उत्तर,पश्चिम के साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी मतदाता बन गए हैं। विपक्ष ने बिहार में एसआइआर के तहत 65 लाख नाम हटाए जाने पर भी वोट चोरी का शोर मचाया था,लेकिन वह ऐसे 65 लोगों को भी सामने नहीं ला पाया था। तथ्य यह भी है कि कांग्रेस नेता कर्नाटक और केरलम में एसआइआर की प्रक्रिया को सही बताकर चुनाव आयोग को धन्यवाद दे चुके हैं। निःसंदेह यह संभव है कि किसी वैध मतदाता का नाम किसी गलती-गफलत से वोटर लिस्ट से बाहर हो गया हो,पर इसका यह अर्थ नहीं कि उसका नाम फिर से शामिल हो ही नहीं सकता। आखिर जब इसकी सुविधा उपलब्ध है,तब फिर वोट चोरी के विपक्ष के राग को बेसुरा और बरगलाने वाला ही कहा जाएगा।

प्रदूषण पर राजनीति का धुआं और जनता की घुटती सांसें



ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

त्योहार खुशियां बांटने के लिए होते हैं,सांसों में जहर घोलने के लिए नहीं। दीपावली प्रकाश,प्रसन्नता,उल्लास और मंगलकामना का पर्व है,लेकिन यदि उत्सव की चमक के पीछे आसमान धुएं से भर जाए, बच्चों और बुजुर्गों का दम घुटने लगे तथा आम आदमी स्वच्छ हवा के लिए तरसने लगे तो हमें अपनी उत्सव परंपराओं और सामाजिक जिम्मेदारियों पर गंभीरता से विचार करना होगा। विडंबना यह है कि आज प्रदूषण जैसी जीवन-मरण की समस्या पर भी राजनीति का धुआं छाने लगा है। जब लोगों की सांसें संकट में हों,तब धर्म,जाति और राजनीतिक विचारधाराओं के चश्मे से समस्या को देखना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है,बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता का प्रमाण भी है। अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता दीया मिर्जा ने पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अपने पर्यावरण अनुकूल दीपावली अभियान में उनका वीडियो जारी किया, लेकिन राजनीतिक विवाद के बाद उसे हटा दिया गया। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाना आखिर विवाद का विषय कैसे बन गया? किसी कलाकार का पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में बोलना किसी धर्म या त्योहार का विरोध कैसे हो सकता है? मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा वीडियो दोबारा जारी करने का निर्देश इस बात का संदेश है कि जनहित की आवाज को राजनीतिक दबाव के आगे दबाया नहीं जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण किसी व्यक्ति, दल या धर्म की जागीर नहीं, बल्कि समूचे समाज की साझा जिम्मेदारी है। मुंबई का उदाहरण इस समस्या की गंभीरता को और उजागर करता है। सामान्यतः समुद्र की हवाओं और भौगोलिक स्थिति के कारण मुंबई को दिल्ली की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर वायु संचार का लाभ मिलता है, लेकिन अब वहां भी प्रदूषण का संकट गहराने लगा है। बीएमसी की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार,मुंबई के 14 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 13 पर पीएम-10 का वार्षिक औसत स्तर राष्ट्रीय निर्धारित सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से अधिक पाया गया। चेंबूर और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में यह स्तर 125 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया। यह केवल आंकड़ा नहीं,बल्कि महानगरीय विकास की उस दिशा पर प्रश्नचिह्न है जिसमें इमारतें तो ऊंची होती जा रही हैं,लेकिन लोगों के हिस्से की स्वच्छ हवा छोटी होती जा रही है। यह समझना आवश्यक है कि मुंबई हो या दिल्ली,प्रदूषण का पूरा दोष केवल दीपावली के पटाखों पर डालकर हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। निर्माण स्थलों से उड़ती धूल, सड़कों पर जमा मिट्टी,वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन,कचरा जलाना और कमजोर शहरी नियोजन इसके बड़े कारण हैं। पटाखे प्रदूषण की समस्या को त्योहारों के दौरान और गंभीर बनाते हैं,लेकिन प्रदूषण का स्रोत वर्षभर सक्रिय रहता है। इसलिए केवल दीपावली के आसपास प्रतिबंध लगाना और फिर शेष वर्ष आंखें मूंद लेना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि मौसमी सक्रियता का प्रदर्शन है। मुंबई में 13 निगरानी केंद्रों का राष्ट्रीय मानक से ऊपर होना बताता है कि समुद्री हवाओं के भरोसे पर्यावरण की रक्षा नहीं की जा सकती। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। सर्दियों की शुरुआत होते ही तापमान में गिरावट, हवा की धीमी गति और वातावरण में प्रदूषकों के ठहराव से वायु गुणवत्ता तेजी से बिगड़ती है। दिल्ली,गाजियाबाद,नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नागरिक हर वर्ष इस जहरीले वातावरण का सामना करते हैं। सुबह की सैर स्वास्थ्य का माध्यम बनने के बजाय जोखिम बन जाती है। बच्चों को खांसी,बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी और पहले से बीमार लोगों को अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिस हवा में जीवन का संगीत होना चाहिए, उसमें जब प्रदूषण का जहर घुल जाए तो विकास के तमाम दावे बेमानी लगने लगते हैं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के अवसर पर केवल प्रमाणित हरित पटाखों की सीमित बिक्री और निर्धारित समय में उनके उपयोग की अस्थायी अनुमति दी है।



प्रतीकात्मक: दैनिक घटती-घटना

7 और 8 नवंबर के लिए निर्धारित समय सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे है। इसके बाद 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध फिर प्रभावी होना है। न्यायालय ने नियमों के उल्लंघन और पारंपरिक पटाखों को हरित पटाखों के नाम पर बेचने से रोकने के लिए सख्त निगरानी पर भी जोर दिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि आदेश कागज पर सख्त और सड़कों पर बेअसर क्यों रह जाते हैं? हरित पटाखों की आड़ में पारंपरिक पटाखों की बिक्री,निर्धारित समय के बाद आतिशबाजी और प्रतिबंधित सामग्री का खुलेआम कारोबार प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलता है। कानून बनाना पर्याप्त नहीं,उसका निष्पक्ष और कठोर क्रियान्वयन भी जरूरी है। यदि नियम तोड़ने वालों को राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक उदासीनता का लाभ मिलता रहा तो न्यायालयों के निर्देश भी धुएं में उड़ते रहेंगे।

दीपावली के उत्सव को सीमित पटाखों,सामूहिक आतिशबाजी और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के साथ भी पूरे उल्लास से मनाया जा सकता है। उत्सव की सार्थकता शोर की तीव्रता में नहीं,बल्कि मन की प्रसन्नता और सामाजिक सद्भाव में है। यह किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं,बल्कि दूसरों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का सम्मान है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब दीया मिर्जा जैसी अभिनेत्री पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हैं तो उनके संदेश को राजनीतिक विवाद में उलझा दिया जाता है। मुंबई उच्च न्यायालय ने 3 नवंबर को बीएमसी को उनका हटाया गया वीडियो दोबारा अपलोड करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि पर्यावरण के मुद्दे को राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग देना अनुचित है। न्यायालय की यह टिप्पणी हमारे लोकतांत्रिक विवेक को झकझोरने वाली है।

आज आवश्यकता है कि सरकारें, न्यायपालिका,नगर निकाय,राजनीतिक दल,उद्योग जगत,सामाजिक संगठन और आम नागरिक एक साझा संकल्प के साथ आगे आएं। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण हो,वाहनों के उत्सर्जन पर कठोर निगरानी हो,सार्वजनिक परिवहन मजबूत बने,कचरा जलाने पर रोक लगे और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की जवाबदेही तय हो। साथ ही नागरिक भी पटाखों के अनावश्यक उपयोग,कचरा जलाने और निजी वाहनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से बचें। अंततः सवाल यह नहीं है कि दीपावली पर पटाखे चलें या न चलें, सवाल यह है कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और सुरक्षित जीवन दे पाएंगे? राजनीति की अपनी जगह है,धर्म और परंपराओं का अपना महत्व है,लेकिन जीवन से बड़ा कोई उत्सव और स्वास्थ्य से बड़ी कोई परंपरा नहीं हो सकती। याद रखना होगा कि प्रदूषण किसी की जाति,धर्म, भाषा या राजनीतिक विचारधारा देखकर फेफड़ों में प्रवेश नहीं करता। हवा सबकी साझा है और उसका संकट भी सबका साझा संकट है। दीपावली के दीप जलें, घर-आंगन रोशन हों,खुशियां बिखरें,लेकिन किसी की सांसों में अंधेरा न उतरे। प्रकाश का पर्व मनाएं,प्रदूषण का पर्व नहीं। यही समय की पुकार है और यही सच्चे उत्सव का विवेकपूर्ण अर्थ है।

जब प्रदूषण पर पहरा ही कागजी हो,तो हवा साफ कैसे हो?

प्रदूषण की बारात निकल रही है,
प्रशासन बैंड बजा रहा है...
हवा जहरीली है,मगर
सरकारी कार्रवाई पूरी तरह स्वस्थ है...



प्रतीकात्मक: दैनिक घटती-घटना

कागजों पर हमारे नियम इतने कड़े हैं कि प्रदूषण करने वाले की साँस रुक जाए। जुर्माने भारी हैं, धाराएँ डरावनी हैं,आयोग बने हुए हैं। लेकिन जमीन पर जाइए तो वही नियम ऐसे लड़खड़ाते नजर आते हैं जैसे बीमार आदमी। सर्दी आते ही दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो जाती है,अदालतें फटकारती हैं,अधिकारी बैठकें करते हैं और फिर सब कुछ वैसा ही चलता रहता है। लगता है प्रदूषण को रोकने से अधिक उसे लेकर चिंता जताने की व्यवस्था विकसित हो गई है। असली सवाल यही है कि नियम इतने सख्त होने के बावजूद उनका पालन इतना कमजोर क्यों है?

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर सात वर्षों में लगभग 12,087 करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन परिणाम उम्मीदों के अनुरूप नहीं मिले। 130 शहरों में से 117 शहर अब भी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों से ऊपर प्रदूषण झेल रहे हैं। केवल 13 शहर ही निर्धारित मानकों तक पहुँच पाए। कई शहरों में तो खर्च के बावजूद प्रदूषण बढ़ गया। आखिर करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी हवा साफ क्यों नहीं हुई? क्या प्रदूषण नियंत्रण का अर्थ केवल योजनाएँ बनाना,बैठकें करना और रिपोर्ट तैयार करना रह गया है? जनता को यह जानने का अधिकार है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ और उससे कितना सुधार आया। सरकारी खर्च की बड़ी रकम अपने आप सफलता का प्रमाण नहीं बन जाती। जब परिणाम हवा में दिखाई न दें,तो योजनाओं की समीक्षा भी उतनी ही कठोर होनी चाहिए जितने कठोर उनके नियम हैं। प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी जिन बोर्डों पर है,उनकी स्थिति भी चिंताजनक है। इन बोर्डों में लगभग 45 प्रतिशत पद खाली हैं। वैज्ञानिकों,इंजीनियरों और निरीक्षकों की कमी से कारखानों तथा प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की नियमित जाँच प्रभावित होती है। यह वैसा ही है जैसे चौकीदार के बिना घर की सुरक्षा की उम्मीद करना। जब निरीक्षक ही नहीं होंगे,तो कारखानों के धुएँ और औद्योगिक कचरे पर निगरानी कौन रखेगा? नियम बनाने वाली व्यवस्था मौजूद है,लेकिन उन्हें लागू करने वाले पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। खाली पद प्रदूषण फैलाने वालों को खुली छूट देते हैं। जब तक संस्थाओं को पर्याप्त कर्मचारी,आधुनिक उपकरण और स्वतंत्र कार्यक्षमता नहीं मिलेगी,तब तक कागजी सख्ती का कोई अर्थ नहीं होगा।

व्यवस्था की असली कमजोरी कार्रवाई के नाम पर होने वाली खानापूर्ति में दिखाई देती है। कई निगरानी केंद्र बंद रहते हैं और निर्माण स्थलों पर नियमों का उल्लंघन जारी रहता है। दिल्ली में निर्माण संबंधी उल्लंघनों पर करोड़ों रुपये के जुर्माने लगाए गए,लेकिन वसूली मुश्किल से छह-सात प्रतिशत ही हो सकी। जुर्माना लगाने में तेजी और वसूली में सुस्ती कैसी सख्ती है? सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2026 में भी स्पष्ट किया कि केवल आदेश जारी करने से समस्या हल नहीं होगी, उनका जमीन पर पालन होना चाहिए। मगर अधिकारी निर्देश जारी करके ही अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं। फाइल में कार्रवाई पूरी हो जाती है,लेकिन सड़क पर धूल उड़ती रहती है। जब उल्लंघन करने वालों को दंड का भय ही नहीं होगा,तो वे नियमों का पालन क्यों करेंगे? प्रदूषण किसी एक शहर या राज्य की समस्या नहीं है,लेकिन इसे रोकने की जिम्मेदारी आते ही सभी अपने-अपने दायरे में सिमट जाते हैं। दिल्ली-एनसीआर के राज्यों ने इस वर्ष निर्धारित कार्ययोजनाओं का केवल 40 से 60 प्रतिशत काम पूरा किया। राजस्थान की प्रगति सबसे पीछे रही,जबकि उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत आगे रहा। एक राज्य पराली जलाने का आरोप लगाता है,दूसरा वाहनों और निर्माण की धूल को जिम्मेदार ठहराता है। दिल्ली अपनी समस्याएँ गिनाती है और पड़ोसी राज्य अपनी मजबूरियाँ। इस आरोप-प्रत्यारोप में प्रदूषण बढ़ता रहता है। आयोगों और बैठकों का कोई विशेष अर्थ नहीं, जब तक साझा कार्ययोजना और जिम्मेदारी तय न हो। हवा राज्य की सीमाएँ नहीं पहचानती,इसलिए उसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी सीमाओं में नहीं बँट सकती। नियमों के कमजोर पड़ने का एक बड़ा कारण कार्रवाई में असमानता भी है। छोटे ठेकेदार या दुकानदार पर कार्रवाई आसान है, लेकिन बड़ी औद्योगिक इकाइयों के मामलों में प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। कहीं कानूनी अपील,कहीं तकनीकी जाँच और कहीं विभागीय अनुमति के नाम पर कार्रवाई टलती रहती है। इस बीच प्रदूषण जारी रहता है। कानून का प्रभाव तभी होगा, जब वह छोटे-बड़े सभी पर समान रूप से लागू होगा। साथ ही,प्रदूषण के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराकर बाकी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पराली के साथ वाहनों का धुआँ, औद्योगिक उत्सर्जन,निर्माण की धूल,कचरा जलाना और सड़कों की खराब सफाई भी प्रदूषण बढ़ाते हैं। समस्या अनेक कारणों से पैदा होती है, इसलिए समाधान भी व्यापक और निरंतर होना चाहिए। अब आवश्यकता नए आदेशों से अधिक पुराने आदेशों के पालन की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के खाली पद भरे जाएँ और निगरानी केंद्र सक्रिय रहें। जुर्मानों की पूरी वसूली हो तथा बार-बार नियम तोड़ने वाली इकाइयों पर कठोर कार्रवाई हो। प्रत्येक विभाग और अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो। योजनाओं पर खर्च और उनके परिणाम सार्वजनिक किए जाएँ। राज्यों के बीच समन्वय बढ़े और प्रदूषण के स्रोतों की नियमित निगरानी हो। अधिकारियों से केवल आदेश नहीं, ठोस परिणाम भी माँगे जाएँ।

प्रो. आरके जैन अरिजीत
बड़वानी,मध्यप्रदेश

दीपावली पर ग्वालिन की पूजा,क्यों करता है ग्वाला समाज ?



आत्माराम यादव
नर्मदापुरम,मध्यप्रदेश

कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाने के लिये सभी यथायोग्य तैयारी करते है वहीं होशंगाबाद सहित आसपास के अनेक गॉवों में बसे ग्वाला दिये के साथ मिट्टी की बनी ग्वालिन को लाकर पूजते है। पिछले 40-45 सालों से मेरे मन में एक सवाल उठता रहा है कि आखिर दीपावली पर मिट्टी की सुन्दर प्रतिमाओं के साथ घोड़े पर सवार युवक को सभी पूजते क्यों है, पर कोई जवाब नहीं मिलता था। नर्मदा पर ग्राम बगवाड़ा में मेरी ननिहाल है बचपन में तीन चार दशक पहले वहॉ के सभी घरों से महिलाएं टोकरी में दूध कन्डे बेचने होशंगाबाद आते। गॉव से नर्मदा नदी तट तक दो ढाई किलोमीटर पैदल चलने के बाद नाव से आते और दूध-दही आदि बेचकर घर के जरूरी सामान ले जाते जिसमें हर त्यौहार की पूजा सामग्री होती। दीपावली पर बाजार से लौटते समय हरेक व्यक्ति या महिला सभी मिट्टी की रंग रोगन की हुई ग्वालिन,घुड़सवार युवक के साथ गायों को सजाने के लिये रंग बिरंगिया घन्टिया,झालरे कोडिया,मोर पंख आदि के साथ रंग लेकर आते यह सिलसिला अब भी जारी है पर साधन आ जाने के बाद सब अलग अलग होकर इस परम्परा का निर्वहन कर रहे है। कच्चे ची मिटटी से बनी इन ग्वालिन के हाथों पर चार दिये और सिर पर एक दिया कुल पॉच दिये बने होते है, जिसपर दीप जलाने की परम्परा भी है। यह दीप ग्वालिन को भगवती शारदा मानकर ऋद्धि सिद्धि की कामना कर उनके सम्मुख प्रार्थना करने से मनोरथ सिद्ध करने का सरल उपाय बताया है।

दीपावली पर ग्वालिन की पूजा की लोकमान्यता ग्वाला समाज को छोड और कहीं देखने को नहीं मिली लेकिन उत्तर भारत में बुन्देलखण्ड,मध्य में मालवांचल सहित गुजरात राजस्थान में अनेक जगह ग्वालिनों को पूजने की परंपरा है। प्राचीन भारत के साहित्य में कालिदास,बाणभट्ट और अश्वघोष ने अपनी रचनाओं में मिट्टी से बनी मूर्ति के लिये हर्षचरित में अंजलिकारिका शब्द प्रयोग किया है वही कादंबरी में मृदंग और पुत्रिका शब्द प्रयोग किया है। दोनों हाथों और सिर के ऊपर मिट्टी का दीया लिये इन सुन्दरतम ग्वालिन की प्रतिमाओं में अगर नीचे की बनावट पर नजर डाले तो वृंदावन की प्रकट लीला में घाघरा घुमा परिधान से लवरेज है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की आल्हादित करने वाली गुहा विद्या की प्रवर्तक माना है। ये ग्वालिनी नित्य सिद्धा है इन्हें कन्या रूप में और परोढ़ा रूप में श्रीकृष्ण ने स्वीकारा है। जिनका विवाह नहीं हुआ है वे कन्याएं है तथा जो ग्वालिनी विवाहित है वे परोढ़ा है। प्रेम भक्ति में परोढ़ाओं को श्रेष्ठ तम मानकर उन्हें नित्य प्रिया,साधन परा और देवी माना गया है। राधाजी के स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ महा भाव स्वरूपा कहा गया है जिनकी आठ परम श्रेष्ठ सखिया ललिता,विशाखा,चंपक कला, ललिता,विशाखा,चंपक कला,चित्रा



प्रतीकात्मक: दैनिक घटती-घटना

सुदेवी, तुंगविद्या,इन्दुलेखा, रंग देवी जो गोपियों व ग्वालिनों में अग्रगण्य है। दीपावली के पूर्व शरदपूर्णिमा की झिलमिलाती रोशनी में महारास में राधाकृष्ण अपनी समस्त कलाओं के साथ महारास करते है और आकाश में चन्द्रमा अपनी चांदनी की छटा से धरा को स्नान करता है। इस रात हर व्यक्ति लक्ष्मी की अगवानी में घर की देहरी पर दीप रखता है और अपने घरों की छतों-मचान पर श्री का प्रतीक खीर रखकर चांदनी से अमृत बरसने की प्रतीक्षा करता है ऐसे ही अवसर पर माता लक्ष्मी धरा पर विचरण को निकलती है।

शरद पूर्णिमा अर्थात महासरस्वती व कार्तिक पूर्णिमा अर्थात महाकाली की बीच की कडी हर मनुष्य को एक दूसरे से जोड़कर रखने वाली कडी है। जैसे शरद का सौन्दर्य श्री का सौन्दर्य है,सीता का सौंदर्य है, राधा का सौंदर्य है, शारदा का सौंदर्य है,वही अलौकिक सौंदर्य नवदुर्गा की भक्ति पूजा अर्चना का भी सौन्दर्य बन जाता है। अश्विन की विजयादशमी को राम रावण का वध कर 20 दिन बाद अयोध्या लौटते है तब उनके राज्याभिषेक में परब्रह्म के रूप में भगवान राम संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ सिंहासन पर विराजते है,अवध झूम उठता है,घर घर दीप प्रज्वलित होते है और यह आनन्द दीपावली के रूप में भारत की संस्कृति में रच बस जाता है। अपवादों के कारण राम सीता को निर्वासित करते है तब राम ब्रह्महत्या के पश्चाताप कर दोष मुक्त करने हेतु गुरू वशिष्ठ से कहते है तब गुरू वशिष्ठ कहते है सीता के बिना यज्ञा पूरा नहीं हो सकेगा और वे सीता को जंगल से लाने की बात करते है तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वाभिमान उन्हें सीता को लाने से रोकता है तब यज्ञ की पूर्ति हेतु स्वर्ण की सीता बनवाकर यज्ञ संपादित कराते है। स्वर्ण से बनी सीता की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात यज्ञ पूर्ण होता है। कहा जाता है स्वर्ण प्रतिमा भगवान से प्रार्थना करती है कि आपका कार्य हो गया है अब आप मुझे पत्नी का सम्मान देकर राजमहल में रहने की इजाजत दे। प्रभु आश्चर्यचकित होते है और कहते है वे एक पत्नी का व्रत रखे है उन्हें पत्नी नहीं बना सकते। स्वर्ण प्रतिमा का हठ के समक्ष वे झुकते है और वचन देते है अगले श्री कृष्ण अवतार में वे उन्हें अपनी सबसे श्रेष्ठ और प्रिय का स्थान देंगे और तब तुम राधा बनकर आयोगी। प्रतिमा हठ करती है तो राम उन्हें श्रोप देते है कि जब राधा के रूप में तुम मिलोगी तो हमारा वियोग होगा और तुम्हें मेरी प्रतीक्षा का वियोग झेलना होगा।

सीता की स्वर्ण प्रतिमा राधा के रूप में अवतरित होती है और कृष्ण की आल्हादिनी शक्ति के रूप में राधा ही श्री कहाती है। जब सीता को निर्वासित किया गया तब वे अन्याय का शिकार हुई पर उन्होंने राम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा,राम सीता के इसी स्वाभिमान के कारण अपने अंदर टूटते गये,पर प्रकट में कहीं भी यह दिखने नहीं दिया। लेकिन कृष्ण अवतार में राधा से मिलने,बिछड़ने का दर्द असीमित था जिसे राधा ने प्रकट नहीं किया। कृष्ण ने वियोगी राधा को आंखों से आंसू न लाने का वचन लिया और राधा के अंतर्मन का दर्द वे समझ सकती थी तभी वे कृष्ण की प्रतीक्षा में रोज अनगिनत दीप जलाकर अपनी स्वर्ण देह को गला कर मिट्टी बन गयी, उधर कृष्ण भी राधा से अलग होने के बाद दोबारा नहीं मिल सके। कृष्ण विछोह के बाद राधा का पूरा जीवन ऐसा हो गया जैसे कोई माटी की मूरत हो। स्वर्ण सीता की मूरत से मूरत बनी राधा के जीवन में बिछोह है। इस विछोह को जन्म-जन्मान्तर से बिदा करने के लिये राधा मिट्टी की ग्वालिन के रूप में अपनी देह पर दीये जलाकर अपने प्रिय की प्रतीक्षा में खड़ी है। यह ग्वालिनी अदृश्य रूप में चैतन्य शक्ति है, श्री जगदम्बा सीता की और श्री राधा की। दीपावली पर हर ग्वाला मिट्टी की गढी हुई इस ग्वालिनी राधा को लक्ष्मी के स्वरूप में पूजता है। दिन बीते,बरस बीते और युग बीते पर आज भी ये ग्वालिनी राधा विरथ राम की राह को प्रशस्त करने तथा सारथी कृष्ण को आश्वस्त कर महामिलन की साक्षी बनने के लिये बार बार मिट्टी में मिलने के लिये माटी से गढ़ी जाती है और बार बार रांधी जाने वाली मिट्टी से स्वरूप लेकर अपने तन पर दीये रखकर जलते हुये अनंत अंधकार को अपने प्रकाश से तिरोहित करती है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

रोशनी

सूर्य क्षितिज के नीचे उतर चुका था। दीपावली की शाम धीरे-धीरे रात में बदल रही थी। हर घर की चौखट पर दीये जगमगा रहे थे। कहीं हँसी थी,



प्रिया देवांगन 'प्रियू'
राजिम,छत्तीसगढ़

कहीं पटाखों की धमक...और इसी रोशनी के बीच एक महल के संगमरमर की चौखट पर रखा दीया अपनी लौ पर कुछ ज्यादा ही इतराता हुआ जल रहा था। उसकी नजर सामने



झोपड़ी के बाहर रखे एक छोटे-से मिट्टी के दीये पर पड़ी।महल वाला दीया मुस्कुराया।

देखा मुझे? शुद्ध घी में जल रहा हूँ। और तुम... तुम्हारे अंदर तो ठीक से तेल भी नहीं है।

झोपड़ी का दीया शांत रहा। महल वाला दीया फिर बोला-मुझे देखो! मालिक ने साफ करके सजाया है। कितनी चमक है मुझमें और तुम्हें देखो...मिट्टी से सने पड़े हो। झोपड़ी का दीया धीरे से बोला-चमक पर इतना अभिमान क्यों? हमारा काम तो एक ही है...अंधेरा दूर करना।

महल वाला दीया हँस पड़ा और गुस्से से बोला-तुम मुझे समझाओगे?

झोपड़ी का दीया बोला लगता है तुम्हें महल का असर हो ही गया है,तुम कब से इंसानों की तरह सोचने लगे;हमें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है।

फिर तुम्हें क्या हुआ? ज्यादा गुस्सा और अकड़ ठीक नहीं है भाई! हमारा काम रोशनी करना है, बस वही कीजिए।

महल का दीया तमतमाया और तेज आवाज में बोला-तुम कौन होते हो मुझे ज्ञान देने वाले। मेरी किस्मत देखो और अपनी देखो। मैं महल में जल रहा हूँ। लोग मुझे देखकर रुकते हैं। तुम तो झोपड़ी के कोने में पड़े हो। तुम्हारी तरफ देखने वाला कौन है? झोपड़ी के दीये की लौ हल्के से काँपी-कभी-कभी भाई...जिसे देखने वाला कोई नहीं होता, वही किसी के सबसे ज्यादा काम आ जाता है। महल वाला दीया ठहाका मारकर हँसा। बड़ी गहरी बातें करने लगे हो।झोपड़ी का दीया हल्का-सा मुस्कुराया और बोला-बात गहरी नहीं है...बस सोच गहरी होनी चाहिए।

महल वाला दीया कुछ कहता,उससे पहले आसमान अचानक गरज उठा। अगले ही पल तेज आँधी चल पड़ी। धूल उड़ने लगी। सूखे पत्ते गलियों में दौड़ने लगे। पेड़ों की डालियाँ झुक गईं। चौखट पर सजे फूल बिखर गए और दीयों की लौ काँपने लगी।

तभी हवा का एक तेज झोंका आया। महल वाला दीया चौखट से नीचे जा गिरा। उसके शरीर में दरार पड़ गई। घी बाहर बहने लगा और उसकी लौ बुरी तरह डगमगाने लगी।मालिक दौड़कर आया। उसने दीया उठाया,दरार देखी और बिना कुछ कहे उसे एक तरफ रख दिया। उधर झोपड़ी का छोटा-सा दीया अब भी आँधी से जूझ रहा था।

उसकी लौ बार-बार झुकती। एक पल को बुझने जैसी होती और अगले ही पल फिर संभल जाती। तभी उसका मालिक दौड़ता हुआ आया। उसने अपने दोनों हाथ दीये के चारों ओर कर दिए। हवा उसकी हथेलियों से टकराती रही। धूल उसके चेहरे पर पड़ती रही, लेकिन उसके हाथ अपनी जगह से नहीं हटे।

महल वाला दीया दूर पड़ा यह सब देखता रहा। कुछ देर पहले तक उसे अपने घी,अपनी चमक और अपने महल पर नाज था।

अब उसकी लौ कमजोर थी...

और सामने वही छोटा-सा दीया था, जिसे वह अपनी औकात से छोटा समझ रहा था। उसने देखा...झोपड़ी का मालिक अपनी हथेलियों से उस छोटी-सी लौ को बचा रहा था,जैसे वह कोई मामूली दीया नहीं, बल्कि उसके घर की आखिरी उम्मीद हो। महल वाले दीये की लौ काँपी। इस बार आँधी से नहीं... पछतावे से।उसने धीमे से कहा–

भाई...आज पहली बार समझ आया। तेरे पास तेल कम था,मगर कोई अपना था। झोपड़ी का दीया कुछ नहीं बोला। उसकी लौ बस हवा में काँपती रही।

महल वाला दीया फिर बोला–

मैं तुझे छोटा समझता रहा...और आज तू ही मेरे सामने सबसे बड़ा बनकर जल रहा है। इतना कहते-कहते उसकी लौ और मद्धम हो गई। झोपड़ी के मालिक ने अपनी हथेलियाँ और कसकर जोड़ लीं।आँधी बाहर थी... लेकिन महल वाले दीये के भीतर कुछ टूट चुका था। उसने आखिरी बार उस छोटी-सी लौ को देखा और बहुत धीमे से बोला-काश...मैंने तेरी रोशनी को तेरे तेल से नहीं,तेरे उजाले से पहचाना होता। उसकी लौ बुझ गई। कुछ देर तक झोपड़ी का दीया अकेला जलता रहा। बाहर आँधी अब भी चल रही थी, लेकिन उसकी छोटी-सी लौ किसी तरह टिकी हुई थी। उसके सामने मिट्टी का घर था...उस घर में शायद महल जैसी चमक नहीं थी,न संगमरमर की चौखट, न शुद्ध घी से भरा दीया।

लेकिन वहाँ किसी की हथेलियाँ थीं,जो उसकी रोशनी बचाने के लिए आँधी से लड़ रही थीं। और शायद यही वह बात थी, जिसे महल वाला दीया बुझने से पहले समझ गया था। किसी घर में जलना बड़ी बात नहीं...

किसी के अँधेरे में उम्मीद बनकर जलते रहना ही असली रोशनी है।

CMYK

बिलासपुर रोड से महामाया रोड और पुराना बस स्टैंड तक पटाखों के भंडारण पर उठ रहा है सवाल,संकरी गलियों में हादसा हुआ तो कौन होगा जिम्मेदार?

हादसे के बाद भी नहीं जागा प्रशासन? शहर के बीच बारूद का खतरा,आखिर किसके संरक्षण में चल रहे गोदाम !

-संवाददाता-
अंबिकापुर,04 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

शहर में पटाखों की दुकानें और गोदाम कहां संचालित हो रहे हैं,उनमें कितना ज्वलनशील और विस्फोटक सामान रखा जा रहा है तथा इन प्रतिष्ठानों को किन शर्तों पर अनुमति दी गई है, यह अब नागरिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल बन गया है। बिलासपुर रोड पर पेट्रोल पंप के आसपास,महामाया रोड से अंदर जाने वाली संकरी गलियों में दुकानों और गोदामों तथा पुराना बस स्टैंड के आसपास ऐसे प्रतिष्ठानों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर घनी आबादी और व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच इस तरह का भंडारण कितना सुरक्षित है? क्या संबंधित विभागों ने कभी मौके पर पहुंचकर इसकी गंभीरता से जांच की है?



अब हादसे का इंतजार नहीं, कार्रवाई जरूरी है...

अंबिकापुर की जनता किसी और भीषण अग्निकांड या विस्फोट के बाद प्रशासनिक सक्रियता नहीं देखना चाहती। शहर के बीच पटाखों के बड़े गोदामों का संचालन किसी भी परिस्थिति में नागरिकों की सुरक्षा से बड़ा नहीं हो सकता। व्यापार करना किसी का भी अधिकार है,लेकिन उस अधिकार की कीमत हजारों नागरिकों की जान को जोखिम में डालकर नहीं चुकाई जा सकती। जिला प्रशासन,पुलिस,नगर निगम,अग्निशमन विभाग और विस्फोटक लाइसेंसिंग प्राधिकरण को संयुक्त अभियान चलाकर शहर के सभी पटाखा प्रतिष्ठानों की जांच करनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन मिलने पर तत्काल सीलिंग,लाइसेंस निरस्तीकरण और वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। सभी थोक भंडारण केंद्रों को आबादी से दूर निर्धारित सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। आखिर प्रशासन किस बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या किसी निर्दोष परिवार की जान जाने के बाद ही जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी? अंबिकापुर को पटाखों के कारोबार से आपत्ति नहीं, बल्कि शहर के बीच बारूद के संभावित खतरे से है। नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस मामले में अब आश्वासन नहीं,जमीन पर दिखाई देने वाली कार्रवाई चाहिए।

23 अप्रैल का अग्निकांड भूला नहीं शहर

अंबिकापुर के ब्रह्मपारा स्थित राम मंदिर रोड पर 23 अप्रैल 2026 को मुकेश प्लास्टिक एवं पटाखा दुकान में लगी भीषण आग को शहर अभी भूला नहीं है। संकरी गली में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया था। पटाखों में हुए धमाकों से आसपास के मकानों तक खतरा पहुंचा और करीब आठ मकान प्रभावित हुए। आग पर काबू पाने के लिए कई स्थानों से दमकल वाहन बुलाने पड़े। गनीमत रही कि इस भयावह घटना में जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि आखिर रिहायशी इलाके में इतनी संवेदनशील सामग्री का भंडारण कैसे हो रहा था?

घटना के बाद कलेक्टर अजीत वसंत ने शहर के सभी पटाखा गोदामों को बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार शहर में आठ स्थायी पटाखा लाइसेंसधारी और दो पटाखा निर्माण लाइसेंसधारी संचालित थे। एसडीएम को गोदामों की स्थिति,अग्निशमन वाहनों की पहुंच, लाइसेंस की शर्तों और सुरक्षा इंतजामों की जांच कर सात दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए थे।

जांच और कार्रवाई पर भी उठे थे सवाल

इस अग्निकांड के बाद पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आई थी। सरगुजा रेंज के तत्कालीन आईजी दीपक कुमार झा ने प्रकरण में विस्फोटक अधिनियम की धाराएं नहीं जोड़े जाने पर एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा था। बाद में एफएसएल जांच में जले हुए पटाखों के अवशेष मिलने की जानकारी सामने आई और प्रकरण में विस्फोटक अधिनियम सहित अन्य धाराएं जोड़ी गईं। यानी जिस घटना को लेकर शुरुआत में कार्रवाई पर सवाल उठे, उसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद विवेचना की दिशा में बदलाव करना पड़ा।

यह घटनाक्रम बताता है कि केवल जांच के आदेश जारी कर देना पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि जांच के निष्कर्ष क्या निकले,जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई हुई और शहर में संचालित अन्य गोदामों को बाहर स्थानांतरित करने के आदेश का कितना पालन हुआ?

फिर वही खतरा,फिर वही इंतजार क्यों?

आज बिलासपुर रोड पर पेट्रोल पंप के आसपास,महामाया रोड की अंदरूनी संकरी गलियों और पुराना बस स्टैंड के आसपास पटाखों की दुकानों एवं गोदामों को लेकर स्थानीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। यदि इन स्थानों पर निर्धारित लाइसेंस से अधिक मात्रा में पटाखों का भंडारण हो रहा है अथवा लाइसेंस में दर्ज स्थान से अलग कहीं स्टॉक रखा जा रहा है,तो यह गंभीर जांच का विषय है। विशेषकर पेट्रोल पंप जैसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों के आसपास ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री के भंडारण की स्थिति का तत्काल सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। संकरी गलियों में दमकल वाहनों का पहुंचना भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में किसी अप्रिय घटना के बाद बचाव कार्य में होने वाली देरी भयावह परिणाम ला सकती है।

क्या कार्रवाई सिर्फ आदेश और कागजों तक सीमित रह गई?

शहर में चर्चा है कि पहले भी बीच शहर में पटाखों से जुड़ी घटना के बाद जांच और कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठे थे। कुछ लोगों का कहना है कि जांच में विस्फोटक नहीं मिलने की बात सामने आई थी और मामला आगे नहीं बढ़ा। हालांकि अप्रैल 2026 के राम मंदिर रोड अग्निकांड में बाद की एफएसएल जांच में पटाखों के अवशेष मिलने और विस्फोटक अधिनियम की धाराएं जुड़ने की खबरें सामने आई थीं। इसलिए जांच के वास्तविक निष्कर्ष और अब तक की कार्रवाई सार्वजनिक करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लोगों की यह टिप्पणी कि 'कुछ नहीं होगा भईया, सब लक्ष्मी जी की माया है' केवल एक व्यंग्य नहीं, बल्कि व्यवस्था के प्रति बढ़ते अविश्वास को भी दर्शाती है।

जनहित में प्रशासन से सीधे सवाल...

* शहर के भीतर संचालित सभी पटाखा दुकानों और गोदामों का भौतिक सत्यापन कब हुआ?
* क्या प्रत्येक प्रतिष्ठान के पास वैध लाइसेंस है और भंडारण उसी स्वीकृत स्थान पर हो रहा है?
* पेट्रोल पंपों और घनी आबादी के आसपास स्थित प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जांच किसने की?
* अप्रैल में गोदामों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के आदेश पर अब तक कितना अमल हुआ?
* सात दिनों में मांगी गई जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया और दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई?
* क्या प्रशासन सभी संवेदनशील गोदामों को तत्काल सील कर सुरक्षित बाहरी क्षेत्र में स्थानांतरित करेगा?

पटवारियों की हड़ताल से धान खरीदी पर संकट के आसार,किसानों का पंजीयन और गिरदावरी अधर में...

-संवाददाता-
अंबिकापुर,04 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

दरिमा ब्लॉक कांग्रेस ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन,अधूरे डिजिटल फसल सर्वे पर जताई चिंता,दरिमा को विकासखंड बनाने और सहकारी बैंक की शाखा खोलने की भी उठाई मांग...





धान खरीदी का सीजन नजदीक आते ही किसानों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। एक ओर 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर पटवारियों की हड़ताल के चलते डिजिटल फसल सर्वे और गिरदावरी का काम अधूरा पड़ा है। इसका सीधा असर किसानों के पंजीयन, धान विक्रय के लिए दर्ज रकबे और पंजीकृत किसानों की सूची पर पड़ने की आशंका है। कई किसानों की गिरदावरी में रकबा शून्य प्रदर्शित होने से धान बेचने को लेकर असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है।

इन समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दरिमा ने पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता एवं ब्लॉक अध्यक्ष नारद गुप्ता के नेतृत्व में सरगुजा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के तत्काल निराकरण की मांग की है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि डिजिटल फसल सर्वे पूरा नहीं होने के कारण पंजीकृत किसानों की सूची संबंधित स्थानों पर चस्पा नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में किसान निर्धारित समयावधि में अपने नाम और दर्ज रकबे का मिलान कर दावा-आपत्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे गंभीर स्थिति उन किसानों की है, जिन्होंने पूर्व वर्षों में धान का विक्रय किया है,लेकिन इस बार गिरदावरी में उनका रकबा शून्य दिखाई दे रहा है। इससे उनके सामने धान विक्रय को लेकर नई परेशानी खड़ी हो गई है।

ज्ञापन में बताया गया है कि पटवारियों की हड़ताल के कारण लगभग 2 से 5 प्रतिशत किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाने की आशंका है। यदि समय रहते सर्वे, गिरदावरी और पंजीयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो ऐसे किसानों को धान बेचने के लिए भटकना पड़ सकता है। धान खरीदी की तारीख नजदीक होने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होना किसानों की चिंता बढ़ा रहा है।

किसानों के साथ बैठक के बाद पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि दरिमा ब्लॉक ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। किसान इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उनका पंजीयन और वास्तविक रकबा धान खरीदी के रिकॉर्ड में दर्ज है भी या नहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों के पीछे पटवारियों की हड़ताल प्रमुख वजह है। सरकार को पटवारियों की मांगों पर तत्काल सकारात्मक पहल करते हुए हड़ताल समाप्त कराने की दिशा में पहल करनी चाहिए,ताकि धान खरीदी के महत्वपूर्ण सीजन में राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित न हों और किसानों को राहत मिल सके।

दरिमा में सहकारी बैंक शाखा और विकासखंड की मांग...

कांग्रेस कमेटी ने किसान संबंधी समस्याओं के साथ दरिमा क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण मांगों को भी प्रशासन के समक्ष रखा है। बैठक के उपरांत दरिमा को विकासखंड घोषित करने तथा यहां सहकारी बैंक की शाखा खोलने के संबंध में अलग-अलग ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया।

सहकारी बैंक की शाखा खोलने की मांग के संबंध में बताया गया कि उपलब्ध पूर्व आंकड़ों के अनुसार दरिमा क्षेत्र की चार समितियों में 10 हजार से अधिक पंजीकृत किसान हैं। वर्तमान में इन किसानों को बैंकिंग लेनदेन के लिए अंबिकापुर स्थित मुख्य शाखा पर निर्भर रहना पड़ता है। अंबिकापुर शाखा पर दरिमा क्षेत्र की चार समितियों के अलावा अंबिकापुर क्षेत्र की छह अन्य समितियों का भी भार है। ऐसे में दरिमा में सहकारी बैंक की शाखा खुलने से मुख्य शाखा का दबाव कम होगा और हजारों किसानों को बैंकिंग कार्यों के लिए अंबिकापुर आने-जाने की परेशानी से भी राहत मिलेगी।

वहीं प्रधानमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन में दरिमा को विकासखंड बनाने की मांग उठाई गई है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि दरिमा क्षेत्र में पहले से ही ब्लॉक स्तर के अधिकांश कार्यालय संचालित हैं। सरगुजा का एकमात्र व्यावसायिक हवाई अड्डा मां महामाया एयरपोर्ट और घुनघुट्टा परियोजना भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं। वर्तमान विकासखंड मुख्यालय अंबिकापुर से दरिमा की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है।

ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक गतिविधियों और स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए दरिमा को स्वतंत्र विकासखंड का दर्जा दिया जाना समय की मांग है। इससे क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं के अनुरूप योजनाओं का निर्माण और उनका स्थानीय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य अनीमा केरकेट्टा,गुरुशरण सिंह, अजीत राम,अरुण गुप्ता, रामसाय मिंज,प्रमेंद्र सरजाल, संजीव कश्यप,रमप्रकाश,जयपाल यादव,नरेश नेटी,रविशंकर नायक, निलेश कश्यप,राकेश सोनी,सुनील किंडो, विकास सिंह,कमल सिंह, पारस राजवाड़े,उमाशंकर कुशवाहा, विनोद सिंह,कमल एक्का,मुनेश्वर बखला सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य उपस्थित थे।



चौपाटी की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने कलेक्टर अजीत वसंत ने दिया सख्त निर्देश

सड़क पर पार्किंग करने वालों पर होगी कार्रवाई...

चौपाटी की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश, सड़क पर पार्किंग करने वालों पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर श्री वसंत ने चौपाटी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शेष निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने तथा चौपाटी में आवश्यक सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से सड़क पर वाहन पार्क करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करने कहा। साथ ही उन्होंने नालियों की नियमित साफ-सफाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्मित शौचालय के बेहतर रखरखाव एवं संचालन के लिए दुकानदारों से मासिक शुल्क लेकर महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से संचालन की व्यवस्था करने कहा।

सुभाष नगर में जल्द शिफ्ट होगी थोक सब्जी मंडी,28 दुकानों का होगा आवंटन

कलेक्टर ने सुभाष नगर स्थित निर्माणाधीन थोक सब्जी मंडी का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति देखी। उन्होंने निर्मित 28 दुकानों का शीघ्र आवंटन करने तथा योजना के अनुसार अतिरिक्त 45 दुकानों का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कंपनी बाजार में संचालित थोक सब्जी मंडी को शीघ्र सुभाष नगर में स्थानांतरित करने पर जोर दिया। साथ ही मंडी परिसर में सड़क,स्वच्छ आकांक्षी शौचालय सहित अन्य निर्माण कार्यों को मिशन मोड में शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

सुभाष नगर में जल्द शिफ्ट होगी थोक सब्जी मंडी,28 दुकानों का होगा आवंटन

-संवाददाता-
अंबिकापुर,04 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

अम्बिकापुर नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति एवं आमजनों की सुविधाओं का जायजा लेने कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने बुधवार को नगर के विभिन्न स्थलों एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चौपाटी, सुभाष नगर स्थित थोक सब्जी मंडी, महामाया कॉरिडोर, महामाया तालाब तथा कांजी हाउस का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने, स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनाने और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री वसंत ने रिंग रोड की समुचित साफ-सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक बजट तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में होने वाले व्यय की 50 प्रतिशत राशि नगर निगम द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि डीएमएफमद से वहन की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त श्री विनय कुमार अग्रवाल सहित नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सामुदायिक स्वास्थ्य मेले का आयोजन,582 ग्रामीणों को मिली सेवाएं

अम्बिकापुर,04 नवम्बर 2026(घटती-घटना। स्वास्थ्य विभाग एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को ग्राम रजपुरी के हाईस्कूल मैदान में एक दिवसीय सामुदायिक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में रजपुरी स्वास्थ्य उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाली चार ग्राम पंचायतों रजपुरी,डेकिडोली,सहनपुर एवं बगडोली के कुल 582 ग्रामीणों ने सहभागिता कर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इनमें बच्चे,महिलाएं,बुजुर्ग एवं युवा सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोग शामिल रहे। स्वास्थ्य मेले का उद्देश्य ग्रामीणों को एक ही स्थान पर स्वास्थ्य जांच,उपचार, परामर्श तथा शासन की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी एवं लाभ उपलब्ध कराना था। इस दौरान ग्रामीणों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाएं प्रदान करने के साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा मितानिन कार्यक्रम की सक्रिय सहभागिता रही। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. पुष्पेंद्र राम,विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.एन. पैकरा एवं विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक दिलीप चंद्रा उपस्थित रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुसू के प्रभारी ने भी आयोजन एवं संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



CMYK

तीनों 95-95-95 लक्ष्यों को हासिल कर सरगुजा बना छत्तीसगढ़ का पहला जिला

एचआईवी एड्स नियंत्रण में सरगुजा की राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि

लगातार दूसरी बार मिला सुरक्षित श्रेणी का सम्मान

-संवाददाता-
अंबिकापुर,04 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के अंतर्गत एचआईवी एड्स नियंत्रण के क्षेत्र में सरगुजा जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित (साफ) श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही सरगुजा छत्तीसगढ़ का पहला जिला बन गया है,जिसने मॉडरेट श्रेणी में सुरक्षित स्थान हासिल किया है।

यह उपलब्धि जिले द्वारा एचआईवी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के निर्धारित तीनों 95-95-95 लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के परिणामस्वरूप हासिल हुई है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा सरगुजा जिले को सुरक्षित श्रेणी में नामांकित करते हुए प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। यह प्रमाण-पत्र कृषि एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री रामविचार नेताम के द्वारा जिलाधीश, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा नोडल अधिकारी को प्रदान किया गया।

यह सम्मान जिले में एचआईवी एड्स की रोकथाम, समय पर जांच, एंटीरेट्रोवायरल उपचार की उपलब्धता तथा वायरल लोड नियंत्रण के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों और प्रभावी कार्यक्रम क्रियान्वयन का प्रमाण है।इस उपलब्धि में जिला प्रशासन,स्वास्थ्य विभाग,जिला एड्स नियंत्रण इकाई, स्वास्थ्यकर्मियों, कार्यक्रम प्रबंधकों तथा सहयोगी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सभी के समन्वित प्रयासों से सरगुजा जिले ने एचआईवी एड्स नियंत्रण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है।

छेनी से वार कर राजमिस्त्री की हत्या,दो आरोपी गिरफ्तार

विवाद के बाद दिया वारदात को अंजाम, आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त छेनी जब्त



-संवाददाता-
अंबिकापुर,04 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रजपुरीकला टिकरापारा में 40 वर्षीय राजमिस्त्री अंगद राम चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने विवाद के बाद छेनी से हमला कर हत्या करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त छेनी भी जब्त की है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस के अनुसार, 2 नवंबर की शाम करीब 7.30 बजे अंगद राम चौधरी का गांव के ही मुकेश चौधरी (23) और धर्मेंद्र चौधरी (26) से विवाद हुआ था। इस दौरान दोनों ने अंगद पर छेनी से सिर और शरीर पर गंभीर वार किए। चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने शव को बाड़ीनुमा स्थान पर फेंक दिया। अंगद राम चौधरी की पत्नी कुछ माह पहले मायके चली गई थी। इसके बाद वह घर में अकेले रहता था, जबकि उसके अन्य परिजन गांव में कुछ दूरी पर रहते थे। परिजनों ने सोमवार रात करीब 10 बजे उसे घर आते देखा था। मंगलवार सुबह उसका शव घर के आंगन में खून से लथपथ मिला। परिजनों की सूचना पर लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की।

पूछताछ में आरोपियों ने कबूला जुर्म

जांच के दौरान पुलिस ने संदेहियों की तलाश कर मुकेश चौधरी पिता श्यामलाल चौधरी और धर्मेंद्र चौधरी पिता स्व. चंदरलाल चौधरी, दोनों निवासी रजपुरीकला टिकरापारा, को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने विवाद के बाद आवेश में आकर छेनी से हमला कर हत्या करना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त छेनी जब्त की गई। मामले में थाना लखनपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) में अपराध दर्ज किया गया है। साक्ष्य मिलने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इनकी रही सक्रिय भूमिका

कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक संपत पोटाई, सहायक उप निरीक्षक मनीष तिवारी, बैजनाथ राम लकड़ा,प्रधान आरक्षक पीतांबर सिंह,विवेक पांडेय तथा आरक्षक दशरथ राजवाड़े, शिवमंगल पैकरा और राजेंद्र लकड़ा शामिल रहे।

महामाया मंदिर में चेन स्नेचिंग करने वाले अंतरजिला गिरोह के चार गिरफ्तार



नवरात्र में महिला के गले से उड़ाई थी 95 हजार रुपए की सोने की चेन,कोरबा जिले के निवासी हैं आरोपी

-संवाददाता-
अंबिकापुर,04 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

नवरात्र के दौरान महामाया मंदिर परिसर में महिला के गले से सोने की चेन चोरी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने अंतरजिला गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से सोने के आभूषण के टुकड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, केदारपुर निवासी ओमप्रकाश जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 अक्टूबर को उनकी पत्नी महामाया मंदिर में दर्शन करने गई थीं। इस दौरान भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात आरोपियों ने उनके गले से सोने की चेन पार कर दी थी। चेन की कीमत करीब 95 हजार रुपए थी। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने धारा 303(2),3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग शहर में चोरी का सोना बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर चार संदिग्धों को हिरासत में लिया। तलाशी में उनके पास से सोने के आभूषण के टुकड़े मिले। पूछताछ में आरोपियों ने महामाया मंदिर में चेन स्नेचिंग की वारदात करना स्वीकार किया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संतोष गिरी (28),पिकू गिरी (25),अमर गिरी (19) और रामकुमार गिरी (32) के रूप में हुई है। सभी ग्राम कौनकोना, ठिहाईपारा, थाना बांगो, जिला कोरबा के निवासी हैं। पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई के बाद आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया।

दीदियों के हुनर से रोशन होगी दीपावली

बलरामपुर,04 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। जिला मुख्यालय बलरामपुर स्थित शनि मंदिर के पास आयोजित बिहान मेले में बुधवार को कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी एक ग्राहक के रूप में पहुंचीं और महिला स्व-सहायता समूहों के स्टॉल से छिंद की टोकरी व माला,मल्टीग्रेन आटा,मिट्टी के दीये तथा ऊन से बने फूल खरीदकर स्थानीय उत्पादों को अपनाने का संदेश दिया। जिला पंचायत सीईओ श्री आशुतोष चतुर्वेदी के साथ उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण कर दीदियों के हाथों से बने उत्पादों की सराहना की।

सरगुजा ओलंपिक : खो-खो व तीरंदाजी में वाड्रफनगर का दबदबा

अर्जुन की तरह लक्ष्य पर रखें नजर,जीत निश्चित है' सरगुजा ओलंपिक के दूसरे दिन कलेक्टर ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह



-संवाददाता-
बलरामपुर,04 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 2026-27 के दूसरे दिन बुधवार को जिला मुख्यालय के विभिन्न खेल मैदानों में खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता था। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखें,जीत निश्चित है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना को सर्वोपरि रखने तथा दृढ़ निश्चय के साथ प्रदर्शन कर जिले को बेहतर स्थान दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी गतिविधि है और आगामी समय में जिले में खेलों के क्षेत्र में और बेहतर कार्य किए जाएंगे। जिला पंचायत सीईओ श्री आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि मैदान पर उतरते ही अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही खिलाड़ी का लक्ष्य होना चाहिए, साथ ही खेल भावना का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है।

दूसरे दिन जूनियर एवं सीनियर वर्ग में फुटबॉल, तीरंदाजी,खो-खो, कराते,कुश्ती एवं बास्केटबॉल की प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। बालक/पुरुष वर्ग के फुटबॉल मुकाबले कृषि विज्ञान केंद्र जाबर तथा बालिका/महिला वर्ग के मुकाबले मिशन स्कूल खेल मैदान में खेले गए। तीरंदाजी,खो-खो,कराते एवं कुश्ती सेजेस हिंदी माध्यम विद्यालय तथा बास्केटबॉल एकलव्य विद्यालय भेलवाडीह के मैदान में संपन्न हुए।

महावीर अस्पताल में फिजियोथेरेपी सहायक बनकर कर रहा था काम,दूसरे व्यक्ति के नाम पर था पंजीयन प्रमाण पत्र

-संवाददाता-
अंबिकापुर,04 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



महावीर अस्पताल में कार्यरत एक फिजियोथेरेपी सहायक के पंजीयन प्रमाण पत्र की जांच के दौरान क्यूआर कोड ने उसकी कथित फर्जी डिग्री की पोल खोल दी। प्रमाण पत्र पर लगा क्यूआर कोड स्कैन करने पर वह झारखंड के एक अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज मिला। इस मामले में गांधीनगर पुलिस ने बिहार निवासी नुरेन आलम (30) के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। अब अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।

मामले का खुलासा 16 अक्टूबर 2026 को जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के महावीर अस्पताल निरीक्षण के दौरान हुआ। निरीक्षण के समय अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों और कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता व पंजीयन संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान फिजियोथेरेपी सहायक के रूप में काम कर रहे नुरेन आलम के पंजीयन प्रमाण पत्र की जांच की गई। प्रमाण पत्र पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करने पर उसकी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर मिली। दस्तावेजों के अनुसार, यह प्रमाण पत्र झारखंड निवासी अभिज्ञान कुमार का था।

जांच में सामने आया कि नुरेन आलम ने दूसरे व्यक्ति की डिग्री में कथित कूटरचना कर उसे अपने दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया था। वह महावीर अस्पताल में करीब 15 दिनों से काम कर रहा था। मामले में अनिल कुमार दास की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने धारा 318(4) में अपराध दर्ज किया।

गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। अभियोजन ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी फरार हो सकता है और साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने प्रकरण के तथ्यों और अभियोजन के तर्कों पर विचार करने के बाद 3 नवंबर 2026 को अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

पेचकस से गले पर वार कर की थी हत्या, जमीन बेचने को लेकर हुआ था विवाद

अंबिकापुर,04 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। पिता की हत्या के मामले में अदालत ने बेटे को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और गवाहों के बयान आरोपी के खिलाफ अहम साबित हुए। अदालत ने माना कि आरोपी धरम सिंह ने अपने पिता रामबिलास सिंह के गले पर लोहे के पेचकस से वार कर उनकी हत्या की थी। मामला सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुनमेरा गुड़ीपारा का है। अभियोजन के अनुसार, 7 मई 2026 को आरोपी धरम सिंह (40) ने पिता रामबिलास सिंह से मां के दशगात्र कार्यक्रम के लिए अपने हिस्से की जमीन बेचने की बात कही थी। पिता ने जमीन बेचने से मना किया तो दोनों के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आरोपी ने पिता के साथ हाथ-मुक्के और लात से मारपीट की। इसके बाद कोड़े से पीटने के साथ लोहे के पेचकस से उनके गले पर वार कर दिया। गंभीर चोट के कारण रामबिलास की मौत हो गई। मामले में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने अदालत में बताया कि मृतक के गले पर धारदार वस्तु से चोट आई थी,जिससे श्वासनली कट गई और दम घुटने से उसकी मौत हुई। डॉक्टर ने यह भी बताया कि जब्त पेचकस से इस तरह की चोट पहुंचना संभव है। वहीं,गवाह ने आरोपी को पिता के साथ मारपीट करते देखने की बात कही थी। पुलिस ने आरोपी के घर से पेचकस,कोड़ा और खून लगा कपड़ा भी जब्त किया था। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार राज की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी ठहराया।

मन की भटकन रोक आत्मचिंतन और परमात्म अनुभूति की ओर बढ़ना ही योग साधना का लक्ष्य : बीके रूपेश भाई

माउंट आबू से पहुंचे प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता एवं पीस ऑफमाइंड टीवी के एंकर के सानिध्य में दो दिवसीय योग साधना शिविर शुरू

-संवाददाता-
अंबिकापुर,04 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से पहुंचे प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता, राजयोग प्रशिक्षक एवं पीस ऑफमाइंड टीवी (पीएमटीवी) के एंकर बीके रूपेश भाई के सानिध्य में बुधवार को नव विश्व भवन,चोपड़ापारा में दो दिवसीय गहन योग साधना शिविर का शुभारंभ हुआ।

इस अवसर पर ब्रह्माकुमारीज अंबिकापुर सेवाकेंद्र की संचालिका राजयोगिनी बीके विद्या दीदी, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रभारी अजय तिवारी,वरिष्ठ पार्षद रमेश जायसवाल एवं उप पुलिस अधीक्षक महालक्ष्मी बहन ने पुष्पगुच्छ भेंटकर बीके रूपेश भाई का स्वागत किया।

स्वागत सत्र में बीके विद्या दीदी ने बताया कि बीके रूपेश भाई की आध्यात्मिक यात्रा अंबिकापुर से ही शुरू हुई थी। यहीं ब्रह्माकुमारीज संस्था के संपर्क में आने के बाद उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा प्राप्त की। आज वे अपनी प्रतिभा और समर्पण से देश-विदेश में आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश प्रसारित कर रहे हैं। मीडिया और आध्यात्मिक प्रसारण के क्षेत्र में भी उन्होंने विशिष्ट पहचान बनाई है।



बीके रूपेश भाई ने कहा कि तपस्या का वास्तविक अर्थ अपने भीतर की ओर लौटना है। संसार की भागदौड़ में भटकते मन और बुद्धि को एकाग्र कर आत्मिक शक्ति जागृत करना ही योग साधना का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से मुक्त होना चाहिए। परमात्मा के सानिध्य में रहकर मन-बुद्धि को संसार के बोझ से मुक्त करना और ईश्वरीय गुणों से जीवन को परिपूर्ण बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि योग तपस्या श्रेष्ठ भविष्य के निर्माण का माध्यम भी है। जब व्यक्ति अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाता है और बुद्धि को सकारात्मक दिशा देता है, तो उसके व्यक्तित्व में दिव्यता और श्रेष्ठता का विकास होता है। केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे जीवन में धारण करना और अनुभव करना ही वास्तविक पुरुषार्थ है।

ईश्वरीय ज्ञान से व्यक्तित्व का आध्यात्मिक उत्थान

उन्होंने कहा कि ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा से व्यक्ति ज्ञानवान, आध्यात्मिक शक्तियों के खजाने से धनवान, चरित्रवान और गुणवान बन सकता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से शिविर को स्वयं में बदलाव लाने और आत्मिक शक्तियों को जागृत करने का अवसर बनाने का आह्वान किया। कुछ समय बाहरी गतिविधियों से अलग होकर आत्मस्वरूप का अनुभव करने तथा परमात्मा से संबंध जोड़कर शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख और आनंद की अनुभूति करने की प्रेरणा दी। शिविर के शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित भाई-बहनों में उत्साह और आध्यात्मिक उमंग दिखाई दी।

नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाया,दुष्कर्म के आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार

पीड़िता गर्भवती, गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को सकुशल बरामदगी के बाद किया गिरफ्तार



-संवाददाता-
अंबिकापुर,04 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में गांधीनगर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़िता को सकुशल बरामद किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी के दुष्कर्म से पीड़िता गर्भवती हो गई है।

पुलिस के अनुसार, 16 फरवरी 2026 को नाबालिग अपने घर से बिना बताए चली गई थी। परिजनों ने तलाश की,लेकिन उसका पता नहीं चला। परिजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताते हुए गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस ने साइबर सेल से तकनीकी जानकारी जुटाई और टीम को पश्चिम बंगाल रवाना किया। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने आरोपी सुजाय मंडल (25), निवासी शिमूलदंगा,थाना शक्तिपुर, जिला मुर्शिदाबाद,पश्चिम बंगाल के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 87, 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शासकीय भवन में पटाखा दुकान, लाइसेंस पर सवाल!

नगर पंचायत ने अनुमति से किया इनकार, तहसीलदार की जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी



पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष का मामला

- जांच में खसरा नंबर 497 की शासकीय भूमि पर दुकान संचालन का उल्लेख
- लाइसेंस 2012 का, नवीनीकरण 2029 तक
- वर्तमान परिसर का स्पष्ट खसरा विवरण लाइसेंस में नहीं





मौके पर पटाखों का भंडारण भी मिला

अब लाइसेंस निरस्तीकरण पर प्रशासन के रुख का इंतजार

लाइसेंस 2029 तक वैध,लेकिन दुकान की अनुमति कहां?

पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के पटाखा कारोबार पर जांच के बाद सवाल

नगर पंचायत ने अनुमति से किया इनकार,तहसीलदार ने कलेक्टर को सौंपी जांच रिपोर्ट...

शासकीय भवन में पटाखों का भंडारण,लाइसेंस की वैधता और परिसर पर उठे गंभीर सवाल...

पटाखा लाइसेंस की जांच में उलझा शासकीय भवन का मामला,अब कलेक्टर के फैसले पर निगाहें

अनुमति नगर पंचायत ने नहीं दी, फिर शासकीय भवन में कैसे चल रही थी पटाखा दुकान?

पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के पटाखा लाइसेंस की जांच में खुली शासकीय भवन की कहानी!

पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के पटाखा लाइसेंस पर जांच की आंच, कलेक्टर तक पहुंची रिपोर्ट

-रवि सिंह-

पटना/बैकुंठपुर,04 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शासकीय संपत्ति पर किसका अधिकार है और सरकारी भवन का उपयोग किसकी अनुमति से हो रहा है,यह सवाल कोरिया जिले के पटना नगर पंचायत क्षेत्र में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष जवाहरलाल गुप्ता से जुड़े पटाखा दुकान प्रकरण में गंभीर रूप से सामने आया है,मामला अब केवल शिकायत और आरोपों तक सीमित नहीं है,शिकायत के बाद तहसीलदार द्वारा की गई जांच का प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा जा चुका है,जांच में सामने आए तथ्यों ने पटाखा अनुज्ञप्ति,दुकान के वास्तविक परिसर और शासकीय भवन के उपयोग की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे दिलचस्प विरोधाभास यह है कि एक तरफ जवाहरलाल गुप्ता के नाम पटाखा विक्रय की अनुज्ञप्ति वर्ष 2029 तक नवीनीकृत बताई गई है, वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत पटना ने लिखित रूप से कहा है कि उसके द्वारा संबंधित शासकीय भवन में पटाखा दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई,तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में भी वर्तमान परिसर के लिए सक्षम अनुमति नहीं मिलने का उल्लेख है,ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब शासकीय भवन में दुकान संचालन की अनुमति ही नहीं थी,तो वहां पटाखा कारोबार किस आधार पर संचालित हो रहा था?

खसरा नंबर 497 की शासकीय भूमि पर दुकान का मामला-तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में संबंधित परिसर को खसरा नंबर 497, रकबा लगभग 0.733 हेक्टेयर की शासकीय भूमि के अंश भाग पर स्थित बताया गया है, रिपोर्ट में जवाहरलाल गुप्ता द्वारा वहां पटाखा विक्रय किए जाने का उल्लेख है,भौतिक सत्यापन के दौरान परिसर में पटाखों का भंडारण पाए जाने की बात भी दर्ज की गई है, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच रिपोर्ट में लाइसेंस के भीतर वर्तमान दुकान परिसर का खसरा नंबर और स्पष्ट भूमि विवरण नहीं मिलने का उल्लेख किया गया है, ऐसे में मूल अनुज्ञप्ति फाइल की जांच और मौके पर संचालित दुकान के परिसर का मिलान बेहद जरूरी हो जाता है, आखिर वर्ष 2012 में लाइसेंस किस स्थान के लिए जारी हुआ था और क्या वर्तमान दुकान उसी स्वीकृत परिसर में संचालित हो रही है?

नगर पंचायत का स्पष्ट जवाब—हमने नहीं दी अनुमति-इस प्रकरण में नगर पंचायत पटना का पत्र भी महत्वपूर्ण है, शिकायतकर्ता द्वारा जानकारी मांगे जाने पर नगर पंचायत ने लिखित जवाब में कहा कि वार्ड क्रमांक 9 स्थित शासकीय भवन में पटाखा दुकान संचालित करने की अनुमति नगर पंचायत द्वारा प्रदान नहीं की गई है,पत्र में यह भी उल्लेख है कि पटाखा विक्रय से संबंधित अनुमति जिला कार्यालय के माध्यम से प्रदान की जाती है,यहीं इस मामले का सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रश्न खड़ा होता है,जिला कार्यालय से पटाखा विक्रय की अनुज्ञप्ति प्राप्त होना और नगर पंचायत की शासकीय संपत्ति पर दुकान संचालित करने की अनुमति मिलना दो अलग-अलग विषय हैं,किसी व्यक्ति के पास पटाखा विक्रय का लाइसेंस होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपनी इच्छा से किसी भी शासकीय भवन में दुकान या गोदाम संचालित कर सकता है, यदि वर्तमान परिसर के उपयोग की कोई अलग अनुमति है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए,और यदि ऐसी अनुमति नहीं है तो शासकीय भवन के उपयोग को लेकर नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए?

जांच में पटाखों का भंडारण, जनसुरक्षा का सवाल भी गंभीर-तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में मौके पर पटाखों का भंडारण पाए जाने का उल्लेख है,दस्तावेजों के साथ परिसर में रखे पटाखों की तस्वीरें भी संलग्न हैं। यह केवल भवन के उपयोग का मामला नहीं रह जाता,बल्कि जनसुरक्षा से भी जुड़ जाता है,पटाखों के विक्रय और भंडारण के लिए विस्फोटक नियमों के तहत निर्धारित परिसर, मात्रा और सुरक्षा शर्तों का पालन आवश्यक है। फायर एक्सटिंग्विशर का प्रमाणपत्र संलग्न होना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन इससे अपने आप यह साबित नहीं होता कि परिसर की स्वीकृति और सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था,संबंधित विभाग को मौके का तकनीकी निरीक्षण कर स्पष्ट करना चाहिए कि भंडारण निर्धारित नियमों के अनुरूप था या नहीं।

जांच रिपोर्ट के बाद लाइसेंस निरस्तीकरण की मांग क्यों?-अब जब जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा जा चुका है और उसमें वर्तमान परिसर के लिए सक्षम अनुमति नहीं मिलने की बात दर्ज है,तब लाइसेंस की समीक्षा का प्रश्न स्वाभाविक रूप से सामने आता है,यदि मूल फाइल के परीक्षण में यह प्रमाणित होता है कि लाइसेंस गलत परिसर के आधार पर जारी हुआ या नवीनीकरण के समय जरूरी जानकारी छिपाई गई,तो सक्षम प्राधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए,इसमें अनुज्ञप्ति के निलंबन या निरस्तीकरण पर विचार भी शामिल हो सकता है,लेकिन यह निर्णय केवल राजनीतिक पहचान, शिकायत या किसी एक निष्कर्ष के आधार पर नहीं,बल्कि मूल दस्तावेजों,लाइसेंस की शर्तों और संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के बाद होना चाहिए,पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष से जुड़ा मामला होने के कारण प्रशासन की निष्पक्षता पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी।

अब कलेक्टर के फैसले की बारी-

इस पूरे प्रकरण में जिला प्रशासन के सामने अब कई सीधे सवाल हैं। क्या लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी से मूल फाइल तलब की जाएगी? क्या स्वीकृत परिसर और मौके पर संचालित दुकान का संयुक्त निरीक्षण होगा? क्या शासकीय सामुदायिक भवन के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति का रिकॉर्ड सामने लाया जाएगा? और यदि जांच में नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है तो क्या लाइसेंस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी? एक तरफ लाइसेंस वर्ष 2029 तक नवीनीकृत है, दूसरी तरफ नगर पंचायत कह रही है कि शासकीय भवन में पटाखा दुकान चलाने की अनुमति उसने नहीं दी, तहसीलदार की जांच में भी सक्षम अनुमति नहीं मिलने का उल्लेख है,ऐसे में अब केवल जांच प्रतिवेदन सौंप देना पर्याप्त नहीं होगा, कलेक्टर को यह स्पष्ट करना होगा कि शासकीय भवन में पटाखा कारोबार किस आधार पर संचालित हुआ और लाइसेंस की शर्तों का पालन हुआ या नहीं, यदि अनियमितता प्रमाणित होती है तो कार्रवाई भी उतनी ही स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए।

शिकायत के बाद हुई जांच,कलेक्टर तक पहुंचा प्रतिवेदन

इस मामले में शिकायतकर्ता अखिलेश गुप्ता ने 27 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर कोरिया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था,शिकायत में आरोप लगाया गया कि वार्ड क्रमांक 9,बाजारपारा स्थित शासकीय सामुदायिक भवन की भूमि और अभिलेखों का उपयोग पटाखा दुकान के संचालन के लिए किया जा रहा है,शिकायतकर्ता ने लाइसेंस की मूल फाइल,भूमि अभिलेख,अनापत्ति प्रमाण-पत्र और दुकान संचालन की अनुमति की जांच कराने की मांग की थी,शिकायत में यह भी मांग की गई थी कि यदि गलत जानकारी या अनियमित दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस प्राप्त किया गया है तो नियमानुसार उसके निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए,इसके बाद तहसीलदार पटना द्वारा स्थल और संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई तथा प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा गया।

लाइसेंस 2029 तक वैध,लेकिन परिसर की वैधता पर सवाल

दस्तावेजों में जवाहरलाल गुप्ता के नाम वर्ष 2012 से संबंधित पटाखा विक्रय अनुज्ञप्ति और उसके नवीनीकरण का विवरण मौजूद है,तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अनुज्ञप्ति वर्ष 2029 तक नवीनीकृत है,लेकिन सवाल लाइसेंस के अस्तित्व का नहीं,बल्कि उस परिसर का है जहां इसका उपयोग किया जा रहा है, यदि लाइसेंस में स्वीकृत परिसर और वर्तमान दुकान का स्थान अलग-अलग है,तो यह जांच का गंभीर विषय है,क्या परिसर परिवर्तन की अनुमति ली गई थी? क्या नवीनीकरण के दौरान मौके का निरीक्षण हुआ था? क्या लाइसेंसिंग प्राधिकारी को वर्तमान भवन की वास्तविक स्थिति की जानकारी थी? इन सवालों का जवाब मूल लाइसेंस फाइल और संबंधित अधिकारियों के रिकॉर्ड से ही मिल सकता है।

अवैध धान परिवहन व भंडारण पर जिला प्रशासन सख्त,अंतरराज्यीय सीमा पर संयुक्त टीमों की कार्रवाई में ट्रक-पिकअप सहित सैकड़ों क्विंटल धान जप्त...

अवैध धान खपाने की कोशिश नाकाम,संयुक्त टीमों ने 406 क्विंटल धान व 780 बोरा किया जप्त



-संवाददाता-

बलरामपुर,04 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले जिला प्रशासन ने अवैध धान परिवहन,भंडारण और बिचौलियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने बताया कि सीमावर्ती एवं आंतरिक चेक पोस्टों पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है तथा दूसरे राज्यों का धान खरीदी केंद्रों में खपाने की कोशिशों को रोकने के लिए राजस्व, खाद्य, मंडी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें सक्रिय हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीदी व्यवस्था में अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वाड्रफनगर तहसील के धनवार चेक पोस्ट पर संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश से लाए जा रहे एक ट्रक व चार पिकअप से लगभग 406 क्विंटल धान पकड़ा। वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर वाहनों को थाना बसंतपुर को सौंपकर मंडी अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट एवं कस्टम मिलिंग उपार्जन आदेश 2016 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। धनवार में ही खली व भूसे के नीचे छिपाकर लाई जा रही 17 बोरी धान से लदा पिकअप भी पकड़ा गया। 3 नवंबर को राजपुर अनुविभाग में संयुक्त टीम ने बिना वैध दस्तावेज परिवहन किए जा रहे 780 बोरा धान जप्त कर थाना राजपुर को सुपुर्द किया। इसी दिन तुगवा-बलंगी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से लाए जा रहे दो पिकअप से 128 बोरी धान जप्त कर बलंगी चौकी में रखा गया। ग्राम तल्केश्वरपुर के पास 63 बोरी धान से लदा पिकअप पकड़कर डिंडो चौकी को सौंपा गया। इसके अलावा झारखंड से अवैध धान ला रहे एक पिकअप को रात्रि लगभग 1 बजे पकड़कर थाना रामचंद्रपुर तथा उत्तर प्रदेश से धान ला रहे एक अन्य पिकअप को थाना रघुनाथनगर के सुपुर्द किया गया। सभी प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

खड़गवां में सड़क मरम्मत के नाम पर हो रही थूक-पॉलिश!

लाखों के काम में गुणवत्ता गायब,बिना सफाई और इमल्शन के बिछाई जा रही डामर की परत

ठेकेदार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का पूरा संरक्षण प्राप्त





-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,04 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

चिरमिरी-कोरबा-बिलासपुर मार्ग पर मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल, निर्माण स्थल से नदारद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी,ठेकेदार की मनमानी से सरकारी राशि के दुरुपयोग की आशंका,खड़गवां चिरमिरी से कोरबा-बिलासपुर मार्ग पर खड़गवां क्षेत्र में इन दिनों सड़क मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है,लेकिन मरम्मत के नाम पर जिस तरह से काम किया जा रहा है, उसने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली और निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं,आरोप है कि सड़क की मरम्मत में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है,सड़क की समुचित सफाई किए बिना ही उसके ऊपर डामरीकरण किया जा रहा है, इतना ही नहीं,सड़क पर इमल्शन का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है, स्थानीय स्तर पर सामने आ रही तस्वीरें और निर्माण कार्य को लेकर उठ रही शिकायतें यह सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर लाखों रुपये की लागत से होने वाला सड़क मरम्मत कार्य गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप कराया जा रहा है या फिर महज खानापूर्ति की जा रही है?

न सफाई,न इमल्शन,फिर कैसे टिकेगा डामर?-सड़क मरम्मत के कार्य में पुरानी सतह की स्थिति के अनुसार आवश्यक सफाई, धूल-मिट्टी और ढीली सामग्री हटाना तथा निर्धारित तकनीकी प्रक्रिया के तहत बिटुमिनस इमल्शन अथवा टैक कोट का छिड़काव करना महत्वपूर्ण होता है,इसके बाद ही डामर की परत बिछाई जाती है। लेकिन खड़गवां में चल रहे मरम्मत कार्य को लेकर आरोप है कि इन जरूरी प्रक्रियाओं की अनदेखी की जा रही है,यदि बिना समुचित सफाई और आवश्यक इमल्शन के डामरीकरण किया जा रहा है,तो नई परत की पकड़ और टिकाऊपन प्रभावित हो सकता है, ऐसी स्थिति में कुछ ही समय बाद सड़क पर डामर उखड़ने,गिट्टियां निकलने और गड्ढे बनने की आशंका बनी रहती है।

निर्माण स्थल से अधिकारी गायब, ठेकेदार की मनमानी पर सवाल-सबसे गंभीर सवाल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं,आरोप है कि सड़क मरम्मत के दौरान विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी नियमित रूप से निर्माण स्थल पर मौजूद नहीं रहता,ऐसे में ठेकेदार द्वारा अपनी मनमर्जी से काम कराए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं,जब विभागीय अधिकारी ही मौके पर रहकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी नहीं करेंगे,तो तकनीकी मानकों का पालन कौन सुनिश्चित करेगा? क्या कार्य की गुणवत्ता की जांच केवल कागजों में होगी या मौके पर भी इसकी वास्तविक पड़ताल की जाएगी? लाखों का भुगतान,लेकिन सड़क मरम्मत में गुणवत्ता कहां? सड़क मरम्मत के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं,ऐसे में जनता का यह जानना जरूरी है कि कार्य की वास्तविक लागत कितनी है,ठेकेदार को किन शर्तों पर काम सौंपा गया है और विभाग द्वारा गुणवत्ता की जांच के लिए क्या व्यवस्था की गई है, यदि निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों की अनदेखी हो रही है,तो यह सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग का गंभीर विषय बन सकता है।

जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांग रहे क्षेत्रवासी-अब सवाल यह है कि लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं? क्या सड़क मरम्मत के कार्य का तकनीकी निरीक्षण कराया जाएगा? क्या निर्माण में इस्तेमाल सामग्री,इमल्शन के छिड़काव और डामर की मोटाई की जांच होगी? क्या संबंधित ठेकेदार को गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए जाएंगे? क्षेत्रवासियों की मांग है कि सड़क मरम्मत कार्य की निष्पक्ष जबकि मरम्मत कार्य कैबिनेट मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है तकनीकी जांच कराई जाए और यदि अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

CMYK



12 किलोमीटर लाइन बनाकर छोड़ दी, चोर तीन किलोमीटर तार ले उड़े! अब विभाग की नींद खुली

टेस्टिंग के बाद 33 केवी लाइन ठप्प, चोरों ने खंभे खाली किए, विभागीय लापरवाही का हिसाब कौन देगा?

बिजली लाइन बनी, चालू नहीं हुई, सरकारी तार चोरी हुआ तो आनन-फानन में जागा विभाग...

पहले लाइन को ठंडे बस्ते में डाला, फिर चोरों ने तार उड़ाया, अब दोबारा खर्च कर रहा विभाग...

एसईसीएल को हैंडओवर से पहले ही तीन किलोमीटर तार चोरी, 12 किलोमीटर की परियोजना पर गंभीर सवाल...

-ओंकार पाण्डेय-

विश्रामपुर/सूरजपुर, 04 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरकारी परियोजनाओं में लापरवाही और जवाबदेही का सवाल अक्सर तब सामने आता है, जब सरकारी धन खर्च होने के बाद भी उसका अपेक्षित उपयोग नहीं हो पाता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित की कार्यप्रणाली से जुड़ा विश्रामपुर का एक मामला भी कुछ ऐसा ही सवाल खड़ा कर रहा है, एसईसीएल विश्रामपुर से गायत्री खदान तक लगभग 12 किलोमीटर लंबी 33 केवी विद्युत लाइन बिछाई गई। लाइन का निर्माण पूरा हुआ, दो से तीन दिनों तक टेस्टिंग के लिए बिजली आपूर्ति भी चालू की गई, लेकिन इसके बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि पूरी परियोजना की रफ्तार थम गई, लाइन बंद पड़ी रही और बताया जा रहा है कि उसे एसईसीएल को हैंडओवर तक नहीं किया गया। हैरानी की बात यह है कि जिस विद्युत लाइन को तैयार करने में विभाग ने संसाधन, श्रम और सरकारी धन खर्च किया, उसकी सुरक्षा और उपयोगिता को लेकर अपेक्षित गंभीरता दिखाई गई या नहीं, यह अब बड़ा सवाल बन गया है, बंद पड़ी इसी लाइन के खंभों से चोरों ने कथित तौर पर करीब तीन किलोमीटर तार पार कर दिया। जब चोरी की जानकारी सामने आई तो विभाग में हलचल मची और आनन-फानन में प्रभावित हिस्से में दोबारा नया तार खिंचवाने का काम शुरू कराया गया, अब सवाल यह नहीं है कि चोरी के बाद तार दोबारा क्यों बिछाया गया, बल्कि सवाल यह है कि आखिर तैयार लाइन को चालू क्यों नहीं किया गया? दो-तीन दिन की टेस्टिंग के बाद आपूर्ति बंद करने की नौबत क्यों आई? और जब लाइन उपयोग में नहीं थी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी?

12 किलोमीटर लाइन तैयार, लेकिन उपयोग के नाम पर सन्नाटा-जानकारी के अनुसार एसईसीएल विश्रामपुर से गायत्री खदान तक लगभग 12 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया था, निर्माण के बाद दो-तीन दिनों तक लाइन को परीक्षण के लिए चालू भी किया गया, इससे यह संकेत मिलता है कि परियोजना कम से कम परीक्षण के स्तर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसके बाद नियमित आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी, यदि लाइन में कोई तकनीकी खामी थी तो उसका निराकरण क्यों नहीं किया गया? यदि एसईसीएल को हस्तांतरण की प्रक्रिया अधूरी थी तो उसे पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए गए? यदि कोई प्रशासनिक या वित्तीय अड़चन थी तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? इन सवालों पर अब तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, एक तरफ बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई लाइनें बिछाने की बात होती है, दूसरी तरफ तैयार लाइन का लंबे समय तक उपयोग में नहीं आना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है, आखिर परियोजना पूरी होने के बाद भी उसका उद्देश्य अधूरा क्यों रह गया?

चोरी के बाद आनन-फानन में नया तार, पहले सुरक्षा क्यों नहीं?-बताया जा रहा है कि चोरी की जानकारी सामने आने के बाद विभाग ने युद्ध स्तर पर प्रभावित हिस्से में नया तार खिंचवाने का काम कराया, यहां भी सवाल उठता है कि जब लाइन पहले से तैयार थी और लंबे समय तक बंद पड़ी रही, तब उसकी सुरक्षा को लेकर विभाग ने पहले गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? यदि चोरी हुए हिस्से में नया तार बिछाना जरूरी था तो इसका खर्च कितना आया? क्या इस अतिरिक्त खर्च का आकलन किया गया? क्या चोरी की घटना के लिए जिम्मेदारी तय की गई? क्या इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई? इन सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, आखिर एक ही परियोजना में पहले तार बिछाने का खर्च, फिर चोरी के कारण नुकसान और उसके बाद दोबारा तार खींचने का खर्च क्यों उठाना पड़ा? यदि समय रहते निगरानी होती तो क्या इस नुकसान से बचा नहीं जा सकता था?

कमीशन के खेल की चर्चा, जांच में सामने आनी चाहिए सच्चाई-परियोजना के लंबे समय तक लंबित रहने को लेकर स्थानीय स्तर पर कमीशन के खेल की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं, हालांकि, इस संबंध में अभी कोई दस्तावेजी प्रमाण या आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस चर्चा को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता, लेकिन जिस तरह तैयार लाइन परीक्षण के बाद बंद पड़ी रही और हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, उससे परियोजना की पूरी कार्यवाही की जांच की मांग उठना स्वाभाविक है, विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि परियोजना के निर्माण से लेकर परीक्षण और हस्तांतरण तक किन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। किस स्तर पर प्रक्रिया रुकी? क्या कोई भुगतान, तकनीकी स्वीकृति, सुरक्षा परीक्षण या अन्य औपचारिकता लंबित थी? यदि सब कुछ नियमानुसार था तो लाइन चालू करने में इतनी देरी क्यों हुई? किसी भी प्रकार की अनियमितता की आशंका को केवल चर्चा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। उसका जवाब रिकॉर्ड, आदेश और तकनीकी दस्तावेजों से दिया जाना चाहिए।

सवालों से बचने के बजाय जवाब दे विभाग-यह मामला केवल तीन किलोमीटर तार चोरी होने तक सीमित नहीं है, यह उस पूरी व्यवस्था पर सवाल है, जिसमें एक परियोजना तैयार होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं हो सका और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी, टेस्टिंग के बाद लाइन बंद क्यों हुई, हस्तांतरण क्यों नहीं हुआ, तार की निगरानी किसके जिम्मे थी और चोरी के बाद ही विभाग सक्रिय क्यों हुआ—इन सवालों का जवाब जरूरी है, 12 किलोमीटर लाइन बिछाने के बाद दो-तीन दिन टेस्टिंग, फिर आपूर्ति बंद, एसईसीएल को हैंडओवर नहीं और इसी बीच तीन किलोमीटर तार चोरी। इसके बाद आनन-फानन में दोबारा तार बिछाने की कवायद, यह पूरी कहानी विभागीय कार्यप्रणाली की समीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग करती है, आखिर सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और परियोजना की जवाबदेही तय करने के लिए क्या किसी बड़े नुकसान का इंतजार किया जाएगा? विभाग को अब केवल नया तार खींचने की जानकारी नहीं, बल्कि पुरानी लापरवाही का पूरा हिसाब भी देना चाहिए।

चोरों ने तीन किलोमीटर तार पार किया, निगरानी व्यवस्था कहां थी?

इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू करीब तीन किलोमीटर तार की चोरी है, बताया जा रहा है कि चोरों ने लाइन के खंभों से तार उतारकर चोरी कर लिया, लगभग 12 किलोमीटर लंबी लाइन में से इतनी बड़ी दूरी का तार गायब हो जाना अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्या लाइन की नियमित निगरानी की जा रही थी? क्या संबंधित क्षेत्र में विभाग का कोई कर्मचारी निरीक्षण करता था? क्या तार चोरी होने की जानकारी तत्काल मिली या काफी समय बाद इसका पता चला? यदि लाइन बंद थी तो क्या विभाग ने उसे असुरक्षित छोड़ दिया था? इन सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों को देना चाहिए, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा केवल कागजों में जिम्मेदारी तय कर देने से पूरी नहीं होती, जमीन पर निगरानी और जवाबदेही भी जरूरी है। तीन किलोमीटर तार की चोरी कोई मामूली घटना नहीं है, यह पता लगाना आवश्यक है कि चोरी किस अवधि में हुई, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ और चोरों तक पहुंचने के लिए क्या कार्रवाई की गई।

बिजली कंपनी और एसईसीएल दोनों की जवाबदेही तय हो...

इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी और एसईसीएल दोनों की भूमिका स्पष्ट होना जरूरी है। बिजली कंपनी को बताना चाहिए कि लाइन का निर्माण कब पूरा हुआ, टेस्टिंग किसकी निगरानी में हुई, आपूर्ति बंद करने का कारण क्या था और हैंडओवर की प्रक्रिया कहां अटकी, वहीं एसईसीएल को भी स्पष्ट करना चाहिए कि उसे लाइन कब और किन शर्तों पर हस्तांतरित की जानी थी तथा हस्तांतरण नहीं होने की वजह क्या रही, इसके अलावा चोरी हुए तार की मात्रा, उसकी अनुमानित कीमत, पुलिस में की गई शिकायत, बरामदगी के प्रयास और दोबारा तार बिछाने में हुए खर्च का पूरा विवरण सामने आना चाहिए, यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

चोरी के बाद नदी, तालाब और जंगल पार कर फिर बिछाई गई केबल

करीब 12 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइन में से लगभग 3 किलोमीटर केबल चोरी होने की घटना के बाद विभाग में हड़कंप मचा, बताया जा रहा है कि चोरी का मामला सामने आने के बाद क्षतिग्रस्त लाइन को दोबारा जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू किया गया, केबल को फिर से बिछाने और जोड़ने के लिए नदी, तालाब और जंगल जैसे कठिन रास्तों से होकर करना पड़ा, मौके की तस्वीरों में श्रमिकों को नदी के किनारे और पानी के बीच केबल खींचते तथा उसे जोड़ने की मशक्कत करते देखा जा सकता है, यह पूरा घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है, जिस लाइन का निर्माण पूरा होने के बाद दो-तीन दिन तक टेस्टिंग की गई थी, वह आखिर उसके बाद बंद क्यों पड़ी रही? टेस्टिंग के बाद लाइन को एसईसीएल को हैंडओवर क्यों नहीं किया गया? यदि लाइन चालू हालत में नहीं थी, तो उसकी सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? करीब तीन किलोमीटर केबल खंभों से चोरी होने तक विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? चोरी के बाद जिस तेजी से विभाग ने नदी, तालाब और जंगल पार कर केबल को दोबारा जोड़ने का काम किया, वही तत्परता यदि पहले लाइन की सुरक्षा और नियमित निगरानी में दिखाई गई होती तो क्या इतनी बड़ी चोरी रोकी जा सकती थी? अब जरूरत केवल केबल जोड़कर लाइन बहाल करने की नहीं, बल्कि चोरी की पूरी घटना, विभागीय लापरवाही और लंबे समय तक लाइन बंद रहने के कारणों की निष्पक्ष जांच की भी है।

मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने की तैयारी तेज, बीएलओ को दिया गया विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का प्रशिक्षण

12 नवंबर से शुरू होगा मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान,

-संवाददाता-

एमसीबी, 04 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में आज जनपद सभा कक्ष मनेन्द्रगढ़ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02 (मनेंद्रगढ़) के बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित प्रक्रिया, दायित्वों एवं निर्धारित प्रपत्रों के उपयोग के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला एमसीबी तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में आयोजित इस प्रशिक्षण में बताया गया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 12 नवंबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने, अपात्र प्रविष्टियों को हटाने तथा मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान वर्ष 2027 के लिए निर्धारित चार अर्हता तिथियों 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर 2027 के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि इन तिथियों को अथवा इससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे युवाओं को मतदाता बनने का अवसर मिलेगा और कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा।

बीएलओ को विभिन्न आवेदन प्रपत्रों के उपयोग की जानकारी देते हुए बताया गया कि फार्म-6 के माध्यम से नए मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा। फार्म-7 का उपयोग मृत एवं स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम विलोपन के लिए किया जाएगा। वहीं फार्म-8 के माध्यम से मतदाताओं के पते में परिवर्तन, नाम एवं अन्य विवरणों में सुधार तथा आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रशिक्षण में सुश्री श्रुति धुर्वे, तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मनेन्द्रगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर टी. विजय गोपाल राव ने बूथ लेवल अधिकारियों को पुनरीक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों, आवेदन प्रपत्रों के सही उपयोग तथा निर्वाचन संबंधी दायित्वों के निर्वहन के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन दिया।

घर बनाने की जल्दबाजी में नाली ध्वस्त, सड़क पर बह रहा घरों का गंदा पानी

पटना नगर पंचायत के बाजारपारा में जलनिकासी व्यवस्था बाधित, लोगों की परेशानी बढ़ी, नाली तोड़ने वाले की जिम्मेदारी या नगर पंचायत की जवाबदेही?

-रवि सिंह-

पटना/कोरिया, 04 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

नगर पंचायत पटना के बाजारपारा में एक अजीबोगरीब स्थिति सामने आई है, यहां एक व्यक्ति द्वारा मकान निर्माण के दौरान कथित तौर पर नाली को ध्वस्त कर दिए जाने से आसपास के घरों का गंदा पानी अब सड़क पर बह रहा है, नतीजा यह है कि मोहल्ले के लोगों को रोजाना गंदे पानी के बीच से होकर आवागमन करना पड़ रहा है, घरों से निकलने वाले पानी की निकासी का रास्ता बंद होने के कारण सड़क ही नाली में तब्दील होती नजर आ रही है, लेकिन अब तक इस समस्या के समाधान की कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि बाजारपारा में मोहम्मद शोएब द्वारा अपने मकान का निर्माण कराया जा रहा है। इसी निर्माण कार्य के दौरान नाली क्षतिग्रस्त कर दी गई, आरोप है कि नाली को तोड़े जाने के बाद उसे दोबारा व्यवस्थित नहीं किया गया, जिसके कारण आसपास के घरों का गंदा पानी सड़क पर फैलने लगा है, इससे स्थानीय लोगों को दुर्गंध, गंदगी और आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

निर्माण की जरूरत अपनी जगह, लेकिन सार्वजनिक सुविधा का नुकसान क्यों?-मकान बनाना किसी भी व्यक्ति का निजी अधिकार है, लेकिन निजी निर्माण के कारण सार्वजनिक नाली और जलनिकासी व्यवस्था बाधित हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, आखिर किसी व्यक्ति के मकान निर्माण की कीमत पूरे मोहल्ले के लोगों को गंदे पानी के बीच आवागमन करके क्यों चुकानी पड़े? यदि निर्माण के दौरान नाली तोड़ी गई है, तो उसे पुनः दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या निर्माणकर्ता की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह सार्वजनिक सुविधा को नुकसान पहुंचने पर उसकी मरम्मत कराए?

नगर पंचायत की जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है?-इस पूरे मामले में नगर पंचायत पटना की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, शहर की नाली, सड़क और जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त रखना नगर पंचायत की जिम्मेदारी है, यदि किसी निजी निर्माण के कारण सार्वजनिक नाली क्षतिग्रस्त हुई है, तो नगर पंचायत को मौके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, संबंधित व्यक्ति को नाली दुरुस्त कराने के लिए निर्देश देना और तब तक जलनिकासी की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना भी जरूरी है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सड़क पर घरों का गंदा पानी बह रहा है और लोगों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है, तब नगर पंचायत की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी होने के बावजूद समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है?

जनता की परेशानी का समाधान कब?-स्थानीय लोगों के लिए यह केवल नाली टूटने का मामला नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्या है, सड़क पर बहता गंदा पानी न केवल आवागमन में बाधा बन रहा है, बल्कि आसपास गंदगी और दुर्गंध की स्थिति भी पैदा कर रहा है, ऐसे में नगर पंचायत को मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल स्थल निरीक्षण कराना चाहिए और नाली की मरम्मत कराकर जलनिकासी बहाल करनी चाहिए, अब देखना यह है कि नगर पंचायत पटना इस समस्या पर कब संज्ञान लेती है और सार्वजनिक नाली को क्षतिग्रस्त करने के मामले में जिम्मेदारी किसकी तय करती है, फिलहाल सवाल सीधा है—मकान निर्माण किसी एक व्यक्ति का है, लेकिन उसकी वजह से परेशानी पूरे मोहल्ले को क्यों उठानी पड़े?



जिस हादसे के बाद ममूटी को घेरने की थी आशंका,वहां बच्चे ने मुस्कुराकर बदला पूरा मंजर,जेब में रखी दो बॉल ने बचाई जान, दोस्त ने बताया किस्सा

अभिनेता वीके श्रीरामन ने ममूटी से जुड़ा 40 साल पुराना किस्सा साझा किया है। ऊटी से कोयंबटूर जाते समय उनकी कार से 10 साल का बच्चा टकराया था,जो चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गया। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी अपनी शानदार अदाकारी के साथ-साथ अपनी शख्सियत के लिए भी जाने जाते हैं। इस साल एक्टर को नेशनल अवॉर्ड और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनसे जुड़े कई पुराने किस्से अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब अभिनेता और लेखक वीके श्रीरामन ने ममूटी से जुड़ा करीब चार दशक पुराना एक ऐसा अनुभव साझा किया है,जिसे पढ़कर लोग हैरान भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। इस किस्से में ममूटी की कार से एक 10 साल के बच्चे को टक्कर लग गई थी। हालांकि,इसके बाद जो कुछ हुआ, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। श्रीरामन ने सोशल मीडिया पर इस घटना को याद करते हुए बताया कि उस समय वह ममूटी के साथ कार में मौजूद थे और दोनों फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में ऊटी से कोयंबटूर जा रहे थे।

ममूटी की कॉन्टेसा कार से हुआ था हादसा

वीके श्रीरामन के मुताबिक यह घटना उस समय की है, जब निर्देशक पवित्रन की फिल्म उत्तरम की शूटिंग ऊटी में चल रही थी। ममूटी और श्रीरामन अपनी यात्रा के दौरान अभिनेता की मशहूर 369 नंबर वाली कॉन्टेसा कार में सवार थे। कार खुद ममूटी चला रहे थे। दोनों ऊटी से पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरते हुए कोयंबटूर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक कॉन्वेंट स्कूल के सामने अचानक एक 10 साल का बच्चा सड़क पार करके बस में चढ़ने के लिए दौड़ा। तभी ममूटी की कार उससे टकरा गई। श्रीरामन ने बताया कि मम्मूटी ने अचानक ब्रेक लगाया,जिससे वह आगे की सीट पर बैठे होने के कारण



कार के शीशे से टकरा गए। हादसे के तुरंत बाद ममूटी कार से बाहर निकले और उनके पीछे श्रीरामन भी उतर आए। उस वक्त उन्हें लगा कि स्थानीय लोग गुस्से में आकर कार में तोड़फोड़ कर सकते हैं और उनके साथ मारपीट भी हो सकती है, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने जो नजारा देखा, वह उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था।

हादसे के बाद बच्चे को देखकर हैरान रह गए दोनों

श्रीरामन ने बताया कि कार की टक्कर से बच्चा सड़क किनारे बनी नाली की तरफ जा गिरा था। कुछ लोग उसे उठाकर उनकी ओर ला रहे थे। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बच्चा बिल्कुल ठीक था और मुस्कुरा रहा था। इसके बाद स्कूल के सिक्योरिटी चीफ ने हादसे के बारे में जो जानकारी दी, उसने सभी को राहत पहुंचाई। वीके श्रीरामन के मुताबिक स्कूल के सिक्योरिटी चीफ ने बताया कि कार की टक्कर बच्चे की दाईं जांघ पर लगी थी। संयोग से बच्चे की पैंट की उसी जेब में दो क्रिकेट बॉल रखी हुई थीं। इन गेंदों की वजह से टक्कर का असर कम हो गया। साथ ही बच्चा सड़क किनारे मौजूद बेलों और झाड़ियों पर गिरा, जिससे उसे गंभीर चोट नहीं आई। सिक्योरिटी चीफ ने इस पूरे घटनाक्रम को किसी फिल्म के स्टंट सीन जैसा बताया। उन्होंने ममूटी की ओर हाथ बढ़ाते हुए उन्हें असली हीरो भी कहा। ममूटी ने भी मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया।

ममूटी ने श्रीरामन से पूछा-डर गए थे क्या?

इस घटना के बाद जब दोनों दोबारा कार में बैठे तो ममूटी ने श्रीरामन से पूछा कि क्या वह डर गए थे। इस पर श्रीरामन ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्हें डर था कि कहीं स्थानीय लोग ममूटी को छोड़कर उन्हें ही ड्राइवर समझकर न पकड़ लें। उन्होंने सोचा था कि लोग उनसे सवाल करेंगे कि स्कूल के पास बच्चे मौजूद होने के बावजूद वह इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे थे। इस पर ममूटी ने भी हाजिरजवाबी दिखाते हुए कहा कि उनके कपड़ों में श्रीरामन बिल्कुल ड्राइवर जैसे लग रहे थे। श्रीरामन ने लिखा कि इसके बाद कोयंबटूर पहुंचने तक वह बार-बार पीछे मुड़कर देखते रहे कि कहीं हादसे में घायल बच्चा और उसके साथ आए लोग उनका पीछा तो नहीं कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर चर्चा में आया पुराना किस्सा

वीके श्रीरामन की यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रही है। उन्होंने करीब 40 साल पुरानी घटना को जिस सहजता और हास्य के साथ याद किया है, वह लोगों को पसंद आ रही है। ममूटी के साथ उनकी पुरानी दोस्ती और उस दिन के अनुभव का यह किस्सा एक अप्रत्याशित हादसे के बाद सामने आए राहत भरे पल को बयां करता है।

बादशाह और श्रेया घोषाल का पहला कोलैब,नया गाना महिया हुआ रिलीज

मशहूर रैपर बादशाह और दिग्गज गायिका श्रेया घोषाल ने बुधवार को नया रोमांटिक गाना महिया रिलीज किया है। संगीत की दुनिया के इन दो दिग्गजों का यह पहला आधिकारिक कोलैबोरेशन है,जिसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। इस गाने को खुद बादशाह ने लिखा है और हितेन ने इसका संगीत तैयार किया है। श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज और बादशाह के मेलोडिक रैप का यह एक अनोखा मेल है। गाने के म्यूजिक वीडियो में मशहूर एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार अवनीत कौर नजर आ रही हैं।



बादशाह ने इसे दो अलग-अलग म्यूजिकल यूनिवर्स का मिलन और एक खूबसूरत यूनिवर्सल लव स्टोरी बताया है। बादशाह ने कहा,सब जानते हैं कि श्रेया जी रोमांटिक गानों की क्वीन हैं। इंडियन आइडल के सेट पर हमारी दोस्ती हमेशा से बहुत अच्छी रही है, लेकिन उस एनर्जी को स्टूडियो में इस गाने के लिए लाना बिल्कुल अलग अनुभव था। बादशाह ने आगे कहा,महिया एक ऐसा गाना है, जिसमें चाहत, प्यार और जश्न का खूबसूरत मेल है। यह गाना हर किसी के मन में बस जाएगा और इसे सुनकर लोगों को ऐसा अहसास होगा कि दो अलग-अलग म्यूजिक की दुनिया के लोग साथ मिलकर यूनिवर्सल लव स्टोरी सुना रहे हैं।÷

एकता कपूर के नए शो 'दिल की बेवफाइयाँ' में पहली बार साथ दिखेंगे गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या

गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या के नए शो को लेकर दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है! बालाजी टेलीफिल्म्स के ऑफिस में दोनों कलाकारों की झलक दिखाकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने के बाद,स्टार प्लस ने अपने बहुप्रतीक्षित शो 'दिल की बेवफाइयाँ' की प्रीमियर डेट का ऐलान कर दिया है। एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित इस रोमांटिक फैमिली ड्रामा में गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या पहली बार पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे। 'अनुपमा'और 'कुंडली भाग्य'जैसे लोकप्रिय शोज के बाद दोनों कलाकार इस नए शो के जरिए एक बार फिर डेली फिक्शन की दुनिया में वापसी कर रहे हैं। 'दिल की बेवफाइयाँ' का प्रीमियर 24 नवंबर को स्टार प्लस पर होगा। शो के लॉन्च को और भी खास बनाते हुए स्टार प्लस ने 'दिल की बेवफाइयाँ' के नौ पोस्टर्स एक साथ जारी किए हैं। टेलीविजन शो के प्रमोशन में अपनी तरह की इस पहली पहल के जरिए दर्शकों को शो की दुनिया की पहली झलक देखने को मिली है। इन नौ पोस्टर्स ने शो के किरदारों,उनके आपसी रिश्तों और कहानी में आने वाले उतार-चढ़ाव को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। गौरव और श्रद्धा की नई जोड़ी को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए एकता कपूर ने कहा,दोनों कलाकारों को दर्शकों से हमेशा भरपूर प्यार मिला है और मैं लंबे समय से



चाहती थी कि ये दोनों एक साथ स्क्रीन पर नजर आएं। अब जब आखिरकार ऐसा होने जा रहा है,तो मैं बेहद उत्साहित हूं,थोड़ी नर्वस भी हूं और अभी से सोच रही हूं कि दर्शक इन दोनों को एक साथ देखकर कैसी प्रतिक्रिया देंगे! एकता कपूर के साथ काम करने और स्टार प्लस पर वापसी को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए गौरव खन्ना ने कहा,मेरे फैंस मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि हम आपको नए शो में कब देखेंगे? और अब मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 'जीके इज बैक!' मेरे फैंस का प्यार और उनका इंतजार मेरी इस वापसी को और भी खास बनाता है। स्टार प्लस पर एक नए शो के साथ लौटना और एकता कपूर के साथ काम करना,मेरे लिए इस नए सफर की एक शानदार शुरुआत है। इस दिवाली मैं इससे ज्यादा और क्या मांग सकता था! सच में ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सही समय पर हो रहा है। अभी के लिए बस इतना कह सकता हूं कि श्रद्धा और मैं कुछ नया लेकर आ रहे हैं। बाकी राज धीरे-धीरे खुलेंगेज तब तक शो को लेकर अंदाजा लगाते रहिए और हम पर अपना प्यार बरसाते रहिए! यह शो दोनों कलाकारों के लिए एक खास प्रोजेक्ट है। जहां श्रद्धा आर्या 'कुंडली भाग्य' के साथ लंबे जुड़ाव के बाद एक बार फिर बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम कर रही हैं,वहीं गौरव खन्ना पहली बार एकता कपूर के साथ किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं।



28 साल बाद नागार्जुन संग दिखेंगी तब्बू, किंग 100 में निभाएंगी दमदार किरदार

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री तब्बू एक बार फिर अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को हैरान करने के लिए तैयार हैं। अभिनेत्री के जन्मदिन के मौके पर उनकी आगामी फिल्म किंग 100 से उनका पहला लुक और विशेष वीडियो जारी किया गया है। इस फिल्म में तब्बू दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी के साथ लगभग 28 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। फिल्म में तब्बू महंती झांसी रानी नाम की एक ताकतवर महिला का किरदार निभा रही हैं,जिसका संबंध शाही परिवार और राजनीति से बताया जा रहा है। उनका गंभीर अंदाज, प्रभावशाली व्यक्तित्व और शानदार लुक दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

जन्मदिन पर मेकर्स ने दिया बड़ा सरप्राइज

चार नवंबर को तब्बू के जन्मदिन के अवसर पर फिल्म निर्माताओं ने उनके प्रशंसकों को खास तोहफा दिया। फिल्म किंग 100 से उनका फर्स्ट लुक पोस्टर और वीडियो जारी किया गया।वीडियो में अभिनेत्री बेहद प्रभावशाली अंदाज में दिखाई दे रही हैं। अलग-अलग साड़ियों में उनका शाही व्यक्तित्व और गंभीर चेहरे के भाव उनके किरदार की ताकत को दर्शाते हैं।फिल्म का निर्माण कर रहे अन्नपूर्णा स्टूडियोज ने सोशल मीडिया पर तब्बू के किरदार की पहली झलक साझा की। निर्माताओं ने अभिनेत्री की प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस की सराहना करते हुए उनके नए किरदार का परिचय कराया।फर्स्ट लुक सामने आने के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है।

महंती झांसी रानी के किरदार में दिखेंगी तब्बू

फिल्म में तब्बू का किरदार महंती झांसी रानी एक प्रभावशाली राजनीतिक महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है।वीडियो में अभिनेत्री को शपथ लेते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही उनके कार्यालय में रखी नामपट्टिका पर किरदार का नाम दिखाई देता है।इस किरदार की सबसे खास बात उसका आत्मविश्वास और भाग्य के बजाय मेहनत पर भरोसा करना है।वीडियो में तब्बू का किरदार स्पष्ट करता है कि वह किस्मत के सहारे सफलता प्राप्त करने की सोच को पसंद नहीं करती।उनके संवाद और हावभाव से संकेत मिलता है कि महंती झांसी रानी राजनीतिक और सामाजिक रूप से बेहद शक्तिशाली महिला होगी। हालांकि, फिल्म में उनके किरदार की पूरी कहानी अभी सामने नहीं आई है।

इस बार रोमांस नहीं, दिखेगी जबरदस्त टक्कर

तब्बू और नागार्जुन की जोड़ी को दर्शक पहले रोमांटिक फिल्मों में देख चुके हैं। लेकिन इस बार दोनों के किरदारों के बीच अलग तरह का संबंध दिखाई देने की संभावना है।फिल्म के नए वीडियो में संकेत दिया गया है कि इस बार दोनों कलाकारों के बीच प्रेम कहानी के बजाय संघर्ष देखने को मिलेगा।इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कहानी में तब्बू का किरदार नागार्जुन के सामने एक मजबूत चुनौती बनकर उभर सकता है।हालांकि,अभिनेत्री फिल्म में मुख्य खलनायिका होंगी या किसी अन्य महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगी, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

28 साल बाद फिर साथ आए तब्बू और नागार्जुन

तब्बू और नागार्जुन की जोड़ी 1990 के दशक में तेलुगु सिनेमा की लोकप्रिय जोड़ियों में शामिल रही है।दोनों कलाकार इससे पहले सिसिंद्री, निन्ने पेल्लाडता और आविडा मा आविडे जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं।विशेष रूप से 1996 में रिलीज हुई निन्ने पेल्लाडता में दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था।अब लंबे अंतराल के बाद दोनों कलाकार एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। यही वजह है कि दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

नागार्जुन की 100 वीं फिल्म है किंग 100

यह फिल्म नागार्जुन के करियर के लिए भी बेहद खास है। किंग 100 को उनकी 100वीं फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।इस उपलब्धि को खास बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं ने बड़े स्तर पर कहानी और प्रस्तुतिकरण की तैयारी की है।इससे पहले अगस्त में नागार्जुन के जन्मदिन पर फिल्म की पहली झलक जारी की गई थी।उस वीडियो में नागार्जुन का एक प्रभावशाली और एक्शन से भरपूर किरदार सामने आया था।

खेल- समाचार

डब्ल्यूपीएल 2027 का शेड्यूल जारी

वडोदरा और मुंबई में होंगे मैच, 14 जनवरी को शुरू होगा टूर्नामेंट, 7 फरवरी को फाइनल

नई दिल्ली,04 नवम्बर 2026। विमेंस प्रीमियर लीग 2027 का शेड्यूल जारी हो चुका है। यह टूर्नामेंट 14 जनवरी को शुरू होगा और फाइनल 7 फरवरी को खेला जाएगा। इस दौरान 25 दिन में कुल 22 मैच खेले जाएंगे। इनमें से शुरुआती 11 मैच 14 जनवरी से 24 जनवरी के बीच वडोदरा में होंगे। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पूर्व चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच होगा। इसके बाद बाकी के 11 मैच मुंबई के ब्रेबॉन स्टेडियम में खेले जाएंगे। यहां 26 जनवरी से 3 फरवरी तक लीग स्टेज के मुकाबले होंगे। इसके बाद प्लेऑफ मैच खेले जाएंगे।

एलिमिनेटर मैच 5 फरवरी को खेला जाएगा

पॉइंट्स टेबल में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगी। लीग स्टैंडिंग में टॉप पर



रहने वाली टीम सीधे फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई करेगी। फाइनल मैच रविवार, 7 फरवरी को ब्रेबोर्न स्टेडियम में होगा। विमेंस प्रीमियर लीग 2027 के सभी 22 मैच शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। पांचों फ्रैंचाइजी दो जगहों पर मैच खेलेंगी।

विमेंस प्रीमियर लीग 2027 के लिए सभी टीमें

दिल्ली कैपिटल्स

एनाबेल सदरलैंड,चिनेल हेनरी,दीया यादव,जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान),किरण नवगिरे,कर्स्टी गॉर्डन,लौरा वोल्वार्ड्ट,लूसी हैमिल्टन,ममता मडिवाला,मारिजाने कप्प,मिन्नू मणि,श्री चरणी,नंदनी शर्मा,नाजमा खान,निकी प्रसाद,शेफाली वर्मा,उमा काश्वी।

गुजरात जायंट्स

अनुष्का शर्मा,एश्ले गार्डनर (कप्तान),बेथ मूनी,भारती फुलमाली,जी.कमालिनी,जॉर्जिया वेयरहम,हैप्पी कुमारी,जितिमणि कलिता, कनिका आहूजा,काशवी गौतम,किम गर्थ,ऑर्ला प्रेंडरगास्ट,राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह,समायरा रघुवंशी,सोफी डिवाइन,तनुजा कंवर,यास्तिका भाटिया।

मुंबई इंडियंस

अक्षिता भगत,अमनजोत कौर,अमेलिया केर,भारती रावल,दिशा कसात,हरमनप्रीत कौर (कप्तान),हेली मैथ्यूज,लतिका इनामदार, नैट साइवर,निकोला कैरी,राहिला फिरदौस,एस सजना,सानिका चालके,संस्कृति गुप्ता शबनिम इस्माइल,श्वेता सहरावत,तारा नॉरिस,वैष्णवी शर्मा।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

अरुंधति रेड्डी,चोल ट्रायन,एलिस पेरी,जॉर्जिया वॉल,जेस जोनसन,लॉरेन बेल,नादिन डीक्लर्क,पूजा वस्त्राकर, प्रत्युषा कुमार,प्रेमा रावत,राधा यादव, ऋचा घोष,सयाली सतघरे,श्रेयंका पाटिल,स्मृति मंधाना (कप्तान),तेजल हसबनिस,वृंदा दिनेश।

यूपी वॉरियर्ज

आशा शोभना,दीप्ति शर्मा,ग्रेस हैरिस,हरलीन देओल,कैथरीन ब्राइस,क्रांति गौड़,मनाली दक्षिणी,मेग लैनिंग (कप्तान),फीबी लिचफील्ड, प्रतीका रावल,सहाना पवार,शिखा पांडे,शिप्रा गिरी,सिमरन शेख,स्नेह राणा,सोफी एक्लेस्टोन,सोफी मोलिन्यू,सुषमा वर्मा।



विराट कोहली ने तोड़ा सचिन का विश्व रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड,04 नवम्बर 2026। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने 38वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले न्यूजीलैंड की धरती पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। बुधवार,4 नवंबर 2026 को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में कोहली ने 51 गेंदों पर 74 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में न्यूजीलैंड को डकवर्थ-लुईस-स्टर्न नियम के तहत पांच विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मुकाबले में कोहली ने सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के एक कीर्तिमान की बराबरी भी कर ली।

मोहन बागान और उड़ीसा एफसी में टक्कर आज

कोलकाता,04 नवम्बर 2026। इंडियन सुपर लीग 2026-27 में गुरुवार,5 नवंबर को फुटबॉल प्रेमियों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। मोहन बागान सुपर जायंट ओडिशा एफसी से भिड़ेगा।

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास)

जिला बलरामपुर-रामानुजगंज मुख्यालय - बलरामपुर (छ0ग0)

फोन नम्बर- 07831-299063 ई-मेल- acbalrampur@gmail.com

:: ई-निविदा आमंत्रण सूचना ::

क्रमांक /2101/निर्माण/आ.वि./2026 बलरामपुर, दिनांक- 23/OCT / 20226

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से निम्नलिखित कार्य के लिए कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बलरामपुर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज में नीचे दर्शाये गये विवरण के अनुसार एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत डी-श्रेणी एवं इससे ऊपर श्रेणी के ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन दर अनुसूची जो दिनांक 10.06.2026 एवं विद्युतीकरण दर अनुसूची जो दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील है, (समस्त संशोधन सहित) एस. ओ. आर. पद्धति में ई-निविदा के माध्यम से प्रतिशत दर पर **प्रथम ई-निविदा** आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 26.10.2026 से दिनांक 20.11.2026 तक प्रभावशील रहेगी ।

क्र.	ऑनलाईन निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	निविदा की राशि	अमानत राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित)
1	2	3	4	5	6
1	201868	जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केन्द्र (TMMCS) का निर्माण ग्राम- दहेजवार विकासखण्ड - बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)	97,08,367	72,900	12 माह
		योग-	**97,08,367**	**72,900**	**12 माह**

निविदा की सामान्य शर्ते एवं अन्य जानकारी वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in/ में देखी जा सकती है।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
बलरामपुर-रामानुजगंज

जी0नं0 -262704370/2

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ- 6/2026-27

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मो0 शमीम अंसारी पिता मोहिउद्दीन अंसारी, उम्र लगभग-48 वर्ष, सिद्दीका परवीन अंसारी पति समीम अंसारी, उम्र- 40 वर्ष दोनों जाति- जुलाहा निवासी इमलीपारा था0तह0 अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा के द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया है, कि आवेदकगण के द्वारा अनावेदक इमकान अंसारी पिता शमीम अंसारी, उम्र-19 वर्ष जाति-जुलाहा निवासी इमलीपारा था0तह0 अम्बिकापुर द्वारा वास्ते मुख्तारआम फरीद खान पिता स्व. रज्जब खान, उम्र- 64 वर्ष जाति - मुसलमान निवासी मोमिनपारा जयनगर, तह0 लटोरी जिला सूरजपुर के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, मोहल्ला- इमलीपारा शीट नं. 08 स्थित नजूल भूमि प्लॉट नं. 2967/1, 2972/1, 2972/2 रकबा क्रमशः 0.002, 0.004, 0.012 हे0 कुल रकबा 0.018 हे0 भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 16.10.2026 के माध्यम से क्रय किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई उक्त भूमि के नजुल अभिलेख में स्वयं का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदकगण द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक - 23 /11/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक- 04/11/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका विनय सोनी आ0/पति स्व. जगदीश प्रसाद सोनी, निवासी मायापुर अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-मायापुर, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1706/3 रकबा 0.061/2 एकड़ भूमि का लोज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 11.11.26 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है । नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः 26.10.26 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0-/ब-121/2026-27

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संजय कुमार धनवानी आ. लक्ष्मण दास व अन्य, निवासी केदारपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित खसरा नंबर 157 / 23 रकबा 0.545 हे. भूमि के नक्शा में हुये त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जॉच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 06/11/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा

आज दिनांकः- 09/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

तहसीलदार
अम्बिकापुर,सरगुजा

नाम परिवर्तन सूचना

मैं मनमेत पति श्री अजय कुमार उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी ग्राम-कैलाशपुर,पोस्ट-जयनगर, तहसील-लटोरी, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) नम्नांकित शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि मेरे पुत्र का सही व वास्तविक नाम सुन्दर लाल (SUNDAR LAL) पिता श्री अजय कुमार है जो कि सही है। जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम मुन्ना राम (MUNNA RAM) दर्ज है जो कि गलत है।

अतः आज से मुझे मेरे पुत्र का वास्तविक नाम सुन्दर लाल (SUNDAR LAL) पिता श्री अजय कुमार के नाम से जाना पहचाना एवं समस्त दस्तावेज में दर्ज किया जाए।

इस संबंध में मेरा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

शपथग्रहिता
मनमेत

महादेव सट्टा,सौरभ चंद्राकर 8 दिन की सीबीआई रिमांड पर

दिल्ली ले जाएगी टीम,12 नवंबर को पेशी,ईडी ने भी रिमांड की मांग रखी

रायपुर,04 नवम्बर 2026। रायपुर की सीबीआई कोर्ट में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को पेश किया गया। कोर्ट ने सीबीआई को 8 दिन की कस्टोडियल रिमांड मंजूर की है। सीबीआई की टीम अब उसे दिल्ली ले जाएगी, जहां उससे अपने ऑफिस में पूछताछ की जाएगी। उसे 12 नवंबर को फिर कोर्ट में पेश करना होगा। कोर्ट में सीबीआई की ओर से बहस के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी और वकील भी मौजूद रहे। ईडी ने भी सौरभ की रिमांड के लिए आवेदन लगाया है। वहीं, सौरभ के वकील तुषार गिरी ने सीबीआई की रिमांड मांग का विरोध किया और इसे गलत बताया।

सौरभ की पेशी को देखते हुए कोर्ट कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बता दें कि करीब 6 हजार करोड़ रुपए के सट्टा घोटाले में आरोपी चंद्राकर को मंगलवार को सीबीआई की टीम दिल्ली से फ्लाइट E6 2307 से रायपुर लेकर पहुंची थी। सीबीआई सौरभ को ओमान से प्रत्यर्पण के बाद भारत लेकर आई है। सोमवार को उसे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर उसे सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।



'सौरभ ने नागरिकता नहीं बदली,भारत का ही नागरिक'

सौरभ के वकील तुषार ने कहा कि उनका पक्ष है कि सौरभ के खिलाफ केवल ईडी के मामले में ही कार्रवाई हो सकती है। सीबीआई के मामले में उनके खिलाफ केस बनने का सवाल ही नहीं उठता, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने ओमान सरकार को पत्र लिखकर सौरभ की नागरिकता के संबंध में जानकारी मांगी थी। ओमान सरकार ने स्पष्ट किया है कि सौरभ भारतीय नागरिक है। उन्होंने मीडिया में चल रही खबरों को निराधार बताते हुए कहा कि कई बातें बिना तथ्यों के प्रसारित की जा रही हैं। महादेव सट्टा ऐप के जरिए करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सट्टे का ऐप है। हो सकता है कि कोई सामान्य परिवार से आता हो तो उसे हम अगल नजरिए से देखते हैं। यदि कोई बड़ी-बड़ी कंपनी शामिल हो जाती है तो उसे हम क्रिकेट इंडिया के लोगो पर देखते हैं।

पूछताछ में कई और नाम सामने आएंगे : सीएम साय

महादेव सट्टा केस में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मुख्य आरोपी को पकड़कर लाया गया है। सीबीआई की पूछताछ में कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए लोकतंत्र की हत्या की और आज वही लोकतंत्र की बात कर रही है।

रवि उप्पल और शुभम सोनी अब तक कहां : बैज

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सौरभ चंद्राकर को भारत लाकर रायपुर पहुंचाया गया,लेकिन रवि उप्पल और शुभम सोनी अब भी पकड़ से बाहर हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 2023 चुनाव में महादेव ऐप को लेकर वीडियो जारी करने वाले शुभम सोनी का अब कोई पता क्यों नहीं है। बैज ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान इस मामले में 72 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई,छापेमारी और गिरफ्तारियां हुईं। तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटाने के लिए केंद्र को पत्र भी लिखा था।

महादेव सट्टा ऐप का को-प्रमोटर रवि उप्पल दुबई से अरेस्ट



महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के को-प्रमोटर और करोड़ों रुपए के अवैध सट्टा सिंडिकेट के आरोपी रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। सौरभ चंद्राकर के ओमान से भारत प्रत्यर्पण के 3 दिन बाद दुबई में ये कार्रवाई हुई है। अधिकारियों के मुताबिक अब उप्पल को प्रत्यर्पित कराकर भारत लाने की कोशिश की जा रही है। एक सप्ताह के भीतर महादेव बेटिंग ऐप मामले में यह दूसरी बड़ी कामयाबी है। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उप्पल के कारोबारी साझेदार और महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से इंडिया लाया था। बुधवार को रायपुर की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सौरभ चंद्राकर को पेश किया गया। कोर्ट ने सीबीआई को 8 दिन की कस्टोडियल रिमांड मंजूर की है। ईडी के आरोपों के अनुसार भिलाई का रहने वाला रवि उप्पल दुबई से ही अपना अवैध कारोबार संचालित करता था। अक्टूबर 2023 में उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया था। इसके बाद दिसंबर 2023 में दुबई के अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया था, लेकिन करीब 45 दिन बाद उसे रिहा कर दिया गया। ईडी ने जनवरी 2024 में ही यूएई से उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था।

प्रत्यर्पण को लेकर आरोपी के वकील ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान सौरभ चंद्राकर के वकील ने ओमान की अदालत के आदेश का हवाला देते हुए सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि भारत की ओर से ओमान को प्रत्यर्पण के लिए जो अनुरोध भेजा गया था, उसमें ईडी के मामले को मंजूरी मिली थी, जबकि सीबीआई के मामले को मंजूरी नहीं दी गई थी।

छत्तीसगढ़ में 3.54 करोड़ का गांजा पकड़ाया

पहाड़ के पास बोरी फेंककर भागे तस्कर,कार की डिक्की में छिपाकर ले जा रहे थे

कोंडागांव,04 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के कांकेर और केशकाल में पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई में करीब 3 करोड़ 54 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। गढ़िया पहाड़ के पास गांजे की 70 बोरियां बरामद की गईं, जिनकी कीमत 1.50 करोड़ रुपए है। पुलिस की घेराबंदी की भनक लगते ही तस्कर गांजा फेंककर भाग निकले। वहीं, केशकाल पुलिस ने एक कार से 407 किलो 910 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 2.03 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने राजस्थान के एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। दोनों मामलों में पुलिस तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रही है।

केस 1-पहाड़ के पास मिला 1.50 करोड़ का गांजा

कांकेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सिगारभाट स्थित गढ़िया पहाड़ के किनारे पुलिस ने लावारिस हालत में गांजे की 70 बोरी बरामद की। इनका कुल वजन 2 क्विंटल 80 किलो और अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। जानकारी के अनुसार, बुधवार को तस्कर ओडिशा से विश्रामपुरी और केशकाल के रास्ते कांकेर पहुंचे थे। गांजा तस्करी की सूचना मिलने पर केशकाल पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। कांकेर पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई थी। दोनों टीमों ने मिलकर कार्रवाई की।



घेराबंदी की भनक लगने पर भागे तस्कर

बताया जा रहा है कि तस्करों को पुलिस की घेराबंदी की भनक लग गई थी। इसके बाद वे गांजे की बोरी पहाड़ के पास फेंककर फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची कांकेर पुलिस ने गांजा जब्त कर लिया। कांकेर एडीओपी हरीश पाटिल के मुताबिक, पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की जांच के दौरान गांजा बरामद किया है। तस्करी में इस्तेमाल की गई दो गाड़ियों की पहचान कर ली गई है। एक कार के ड्राइवर को भी चिह्नित किया गया है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है।

केस 2-कार में मिला 2.40 करोड़ गांजा

दूसरी कार्रवाई में केशकाल पुलिस ने 3 नवंबर को सूचना के आधार पर एक कार (ओडी-10-वी-7053) को रोककर तलाशी ली। कार से 407 किलो 910 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 2 करोड़ 3 लाख 95 हजार 500 रुपए आंकी गई है। गांजा 78 पैकेट में मिला, जो ड्राइवर सीट के पीछे और डिक्की में टेप से लपेटकर रखे गए थे। ड्राइवर ने पूछताछ में अपना नाम दीपक कुमार माली (31) बताया। वह राजस्थान का रहने वाला है।

कार की एक्स्ट्रा नंबर प्लेट भी मिली

पुलिस को कार के डैशबोर्ड में छिपाकर रखी गई एक एक्स्ट्रा नंबर प्लेट भी मिली, जिस पर आर-23-यूबी-8472 लिखा था। आरोपी के पास से रेडमी मोबाइल फोन और 1,100 रुपए नकद भी बरामद किए गए।

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

पुलिस ने गांजा, कार, मोबाइल और अन्य सामान समेत कुल 2 करोड़ 18 लाख 96 हजार 600 रुपए की संपत्ति जब्त की। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। अदालत में पेश किए जाने के बाद उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। स्कपंकज चंद्रा के निर्देश पर जिले में गांजा और शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई में केशकाल थाना प्रभारी रितेश मिश्रा सहित उपनिरीक्षक कंवल सिंह शोरी,सहायक उपनिरीक्षक भगत सिंह नेताम,सुरेश मरकाम,प्रधान आरक्षक ईश्वर नेताम,संजय बिसेन और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

छत्तीसगढ़ में मकड़ियों की दो नई प्रजातियों का पहला राज्य रिकॉर्ड...ऋषिझरन जंगल में मिलीं दुर्लभ मकड़ियां

रायपुर,04 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के जैव विविधता से समृद्ध जंगलों में मकड़ियों की दो महत्वपूर्ण प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र स्थित ऋषिझरन जंगल में किए गए शोध के दौरान जाल बनाने वाली मकड़ियों की दो प्रजातियां स्टीटोडा सिंगुलटा (थोरेल,1890) और थेरिडुला गोनीगैस्टर (साइमन, 1873) मिली हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में इन दोनों प्रजातियों और इनके संबंधित वंश का यह पहला आधिकारिक और वैज्ञानिक रिकॉर्ड है। इन मकड़ियों की खोज से जुड़ा आधिकारिक शोध अध्ययन अक्टूबर 2026 में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं द्वारा देवभोग क्षेत्र के जंगलों में किए गए फील्ड सर्वे के दौरान इन्हें एकत्र किया गया था। यह महत्वपूर्ण खोज छत्तीसगढ़ के स्थानीय प्राध्यापकों और वन्यजीव शोधकर्ताओं की एक संयुक्त टीम द्वारा की गई है।

शोध दल में डॉ. अविनाश आर. निचाट-असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (प्राणी शास्त्र विभाग),एम.वी.वी. शासकीय स्नातकोत्तर महा विद्यालय, भखारा,धमतरी,हितेश कुमार वारते शोधार्थी (लाइफ साइंस विभाग), श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, रायपुर,माणिक चंद बंजारे अतिथि व्याख्याता (प्राणीशास्त्र विभाग), शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय खैरागढ़ एवं शासकीय नवीन महाविद्यालय आमदी (धमतरी) तथा यशवंत नायक शोधार्थी (प्राणीशास्त्र विभाग),शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर शामिल थे।



यह अध्ययन मकड़ियों के वर्गीकरण एवं भौगोलिक वितरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विशेष बात यह है कि इन दोनों प्रजातियों के साथ इनके संबंधित वंश स्टीटोडा और थेरिडुला का भी छत्तीसगढ़ में पहली बार रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। शोध के दौरान दोनों प्रजातियों को गरियाबंद जिले के देवभोग स्थित ऋषिझरन वन क्षेत्र से हाथों द्वारा एकत्रित किया गया। यह वन क्षेत्र ओडिशा की सीमा के समीप स्थित है। इन दोनों मकड़ियों की शारीरिक बनावट भी इन्हें एक-दूसरे से अलग पहचान देती है। स्टीटोडा सिंगुलटा का उदर गहरे चॉकलेटी रंग का होता है, जिसके अगले हिस्से में पीले रंग की एक रेखा पाई जाती है। वहीं, थेरिडुला गोनीगैस्टर का उदर कालेपन लिए होता है, जिस पर पांच पीले रंग के विशिष्ट धब्बे दिखाई देते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, छत्तीसगढ़ में अब तक जाल बनाने वाली मकड़ियों की प्रजातियों का सीमित दस्तावेजीकरण हुआ है। ऐसे में इन दोनों प्रजातियों का रिकॉर्ड राज्य की जैव विविधता और मकड़ियों के भौगोलिक वितरण संबंधी वैज्ञानिक जानकारी को समृद्ध करेगा।

छत्तीसगढ़ के शिक्षक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

मर्जर से पहले की सर्विस पेंशन में जोड़ने की मांग,दीपावली के बाद होगी सुनवाई



रायपुर,04 नवम्बर 2026। मर्जर से पहले शिक्षा कर्मी के रूप में दी गई सर्विस को पेंशन की गणना में शामिल करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। शिक्षकों ने पुरानी सर्विस को पेंशन के लिए मान्य करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। इसमें रामलाल डड़सेना एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन का मामला शामिल है। शिक्षकों का तर्क है कि उन्होंने मर्जर से पहले कई साल तक सरकारी नियंत्रण में सर्विस दी है। ऐसे में उस अवधि को पेंशन की गणना से बाहर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशुतोष गढ़े ने बताया कि याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया है। दीपावली के बाद मामले में सुनवाई होने की संभावना है।

हाईकोर्ट ने 120 दिन में पॉलिसी बनाने कहा था...

शिक्षकों के मुताबिक, इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शासन को मर्जर से पहले की सर्विस को पेंशन के लिए मान्य करने के संबंध में पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मर्जर से पहले की लंबी सर्विस को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शासन को सर्विस की निरंतरता, काम की प्रकृति और प्रशासनिक नियंत्रण जैसे पहलुओं पर विचार कर 120 दिनों के भीतर कारण सहित फैसला लेने कहा गया था। शिक्षकों का आरोप है कि शासन ने इस निर्देश के बाद भी कोई नई पॉलिसी नहीं बनाई।

1 जुलाई 2018 को हुआ था मर्जर

प्रदेश में शिक्षा कर्मियों को 1 जुलाई 2018 से सरकारी शिक्षक के रूप में मर्ज किया गया था। शिक्षकों का कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने कई वर्षों तक लगातार सर्विस दी है। इसके बावजूद पेंशन की पात्रता तय करते समय केवल मर्जर के बाद की सर्विस को गिनना उनके साथ भेदभाव है। उनका तर्क है कि यदि 10 साल की सर्विस की गणना केवल मर्जर की तारीख से की जाएगी तो कई शिक्षक 2028 के बाद ही पेंशन के पात्र हो पाएंगे, जबकि वे इससे पहले ही लंबे समय तक सर्विस दे चुके हैं।

विज्ञान,तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में करेंगे स्थापित : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर,04 नवम्बर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ ज्ञान, विज्ञान,तकनीक और नवाचार की शक्ति से समृद्ध बनाना राज्य सरकार का संकल्प है। हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ को केवल औद्योगिक और आर्थिक विकास में ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च शिक्षा, आधुनिक प्रौद्योगिकी और चिकित्सा नवाचार के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्ध खनिज संपदा, ऊर्जा संसाधनों, औद्योगिक संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़कर विकास का एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में भारतीय विज्ञान संस्थान,बेंगलुरु के निदेशक प्रोफेसर जी.रंगराजन एवं संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों तथा राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में छत्तीसगढ़ को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा,कौशल विकास और चिकित्सा अनुसंधान के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान भारतीय विज्ञान संस्थान और छत्तीसगढ़ शासन के बीच तीन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर संभावित सहयोग, आवश्यक वैज्ञानिक अधोसंरचना, संस्थागत व्यवस्थाओं और क्रियान्वयन की प्रारंभिक रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई।



मुख्यमंत्री साय ने भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों का छत्तीसगढ़ आगमन पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय विज्ञान संस्थान देश ही नहीं, विश्व के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों में शामिल है। इसकी विशेषज्ञता, अनुसंधान क्षमताओं और शैक्षणिक अनुभवों का लाभ छत्तीसगढ़ के विश्व विद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, उद्योगों,स्वास्थ्य सेवाओं और विशेष रूप से युवाओं को मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी,अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल नवाचार और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में वैज्ञानिक अनुसंधान,तकनीकी उत्कृष्टता और उच्च कौशलयुक्त मानव संसाधन की निर्णायक भूमिका होगी। छत्तीसगढ़ भी इसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी विश्वस्तरीय वैज्ञानिक और शैक्षणिक अधोसंरचनाएं विकसित करना चाहती है,जिनका लाभ केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित न रहे,बल्कि आने वाली अनेक पीढ़ियों को प्राप्त हो। विज्ञान और अनुसंधान में निवेश प्रदेश के दीर्घकालिक विकास, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य में निवेश है। मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ केवल बड़े शहरों और प्रमुख शिक्षण संस्थानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बस्तर, सरगुजा सहित प्रदेश के ग्रामीण, जनजातीय और दूरस्थ अंचलों में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इन प्रतिभाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और तकनीकी प्रशिक्षण के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की है।

अमित जोगी 9 नवंबर को थाने में होंगे पेश...पार्टी बोली...फरार होने की खबरें भ्रामक,निजी कार्यक्रम के चलते प्रदेश से बाहर हैं

रायपुर,04 नवम्बर 2026। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी के फरार होने की खबरों को पार्टी ने भ्रामक बताया है। पार्टी का कहना है कि अमित जोगी 2 से 8 नवंबर तक पहले से तय निजी कार्यक्रम के चलते प्रदेश से बाहर हैं। वे 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ लौटने के बाद खुद थाने पहुंचकर अपना पक्ष रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री निलेश चौहान ने आज थाना प्रभारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमित जोगी की ओर से ई-मेल के माध्यम से भेजा गया जवाब और उनका पक्ष पुलिस के सामने रखा। पार्टी ने कहा कि अमित जोगी के पूर्व निर्धारित निजी कार्यक्रम को एफआईआर से जोड़कर उनके फरार होने की खबरें फैलाना गलत है। पार्टी कानून का सम्मान करती है और उसे न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सांकेतिक रूप से शादी और हनीमून के दृश्यों में दिखाया गया था। वीडियो को लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई। इसे प्रधानमंत्री और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान बताया। इसके विरोध में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रायपुर के सिविल लाइंस थाने पहुंचकर अमित जोगी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। विधायक राजेश मूणत ने कहा कि, वीडियो में प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त के किरदारों को लेकर बेडरूम के दृश्य दिखाए गए हैं। उन्होंने वीडियो की पटकथा लिखने वालों,इसे बनाने वाले कैमरामैन और इसमें भूमिका निभाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की।



हाईकोर्ट बोला-बेहतर शिक्षा से ज्यादा जरूरी बच्चे का हित...बेटे ने पिता को देखा तक नहीं,दूसरी शादी कर चुके शिक्षक को नहीं मिली कस्टडी

बिलासपुर,04 नवम्बर 2026। हाईकोर्ट के जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत ने बच्चे की कस्टडी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। डिवीजन बेंच ने पिता अपील खारिज करते हुए कहा कि केवल शिक्षक होना और बेहतर शिक्षा देने की क्षमता रखना बच्चे की कस्टडी का आधार नहीं हो सकता। मां के साथ रह रहे बच्चे की देखभाल और पढ़ाई में कोई लापरवाही साबित नहीं होने पर उसे मौजूदा माहौल से हटाना उचित नहीं होगा। मामला बलौदाबाजार जिले का है। बलौदाबाजार निवासी टीचर पति ने पत्नी से विवाद के बाद तलाक ले लिया। फिर उसने ने दूसरी रचा ली। इधर, बचपन से पिता के प्यार से अनजान बेटे की उसने कस्टडी मांगी।

फैमिली कोर्ट में सात साल के बेटे ने पिता की तरफ देखा तक नहीं। उसने पिता के साथ जाने की इच्छा भी नहीं जताई तो कोर्ट ने बेटे की कस्टडी देने से इंकार कर दिया। इस दंपती की शादी 28 अप्रैल 2015 को हुई थी। उनका एक बेटा है। इस दौरान पति-पत्नी में झगड़ा शुरू हुआ तो पति ने तलाक ले लिया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)